सांध्य दैनिक

श्रीकंचनपथ

लीपा पोती नहीं सिर्फ सच

RNI. Reg. No. CHHHIN/2009/30534
डाक पंजीयन क्रं.-छ.ग./दुर्ग/1000000029/2026-28

वर्ष- 17 अंक - 56 | www.shreekanchanpath.com | संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल | भिलाई, मंगलवार 09 दिसंबर 2025 | पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

खास-खबर

छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड, 4 शहरों में 10 डिग्री से नीचे तापमान

रायपुर। उत्तर से आ रही हवा के कारण छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने सरगुजा, दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर संभाग के जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। चार शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। इनमें मैनपाट, अंबिकापुर, पेंड्रा और जगदलपुर शामिल हैं। मैनपाट में रात का पारा 4एष्ट से नीचे चला गया है और वहां ओस की बूंदें जमकर बर्फमें बदल गई हैं। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 5एष्ट, पेंड्रा में 8एष्ट और जगदलपुर में 9.8 डिग्री दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक तापमान 30.4 डिग्री रायपुर में और सबसे कम न्यूनतम तापमान 5 डिग्री अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया।

मॉर्निंग वॉक कर रहे बुजुर्ग पर भालू का हमला

मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर। जिले के अलग-अलग गांवों में भालू का आतंक जारी है। 9 दिसंबर की सुबह मनेंद्रगढ़ शहरी क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक कर लौट रहे एक बुजुर्ग पर भालू ने हमला कर उन्हें घायल कर दिया। इसके बाद एक मादा भालू अपने दो शावकों के साथ वनवासी कन्या छात्रावास में घुस गई, जिससे छात्राएं डर में इधर उधर भागने लगी। स्थानीय लोगों ने भालू का वीडियो भी बनाया है। जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह घटना वार्ड नंबर 17 के निवासी दिलबरण प्रसाद के साथ हुई। भालू के हमले में घायल हुए दिलबरण प्रसाद को मनेंद्रगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। हमले के कुछ देर बाद ही वही मादा भालू अपने दो शावकों के साथ वनवासी कन्या छात्रावास परिसर में दाखिल हो गई। भालू के डर से छात्रावास की छात्राएं बाहर नहीं निकल पा रही थी और अंदर ही फंसी रही। बाद में जब भालू वहां से निकले तो सभी ने राहत की सांस ली।

पूर्व सीएम के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर बहस पूरी

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की याचिका पर हाईकोर्ट में बहस पूरी हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और चैतन्य बघेल के पक्षों की सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।शराब घोटाला केस में गिरफ्तार चैतन्य बघेल 18 जुलाई से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। चैतन्य की ओर से अदालत में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए राहत की मांग की गई थी। वहीं ईडी ने अपने पक्ष रखते हुए चैतन्य के खिलाफदर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर विस्तार से तर्क दिया। इस अहम मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच में हुई। न्यायालय की तरफसे फैसला सुरक्षित रखने के बाद अब राजनीतिक और प्रशासनिक हल्कों में फैसले को लेकर कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं।

एसआईआर के काम में 'बाधा' पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- ईसी संज्ञान में लाए

सुप्रीम कोर्ट ने कहा आवश्यकता पड़ी तो हम करेंगे आदेश

श्रीकंचनपथ डेस्क

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) को धमकाने के अलावा चुनाव आयोग की तरफसे कराए जा रहे मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के काम में कथित तौर पर बाधा डालने की घटनाओं को गंभीरता से लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग संज्ञान में लाए आदेश देने का काम कोर्ट करेगा।

शीर्ष अदालत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग से मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सहयोग की कमी को गंभीरता से लेने को कहा। सर्वोच्च अदालत ने कहा, अगर हालात और बिगड़ते हैं तो पुलिस तो तैनात करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि उनके पास सभी सांविधानिक शक्तियां हैं, जिससे हम बीएलओ और अन्य अधिकारियों को धमकाने की घटनाओं से डील कर सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे निपटें वरना इन हालातों से अराजकता हो सकती है।

ईसी ने बंगाल के लिए नियुक्त किए पांच आईएएस

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर के कामकाज की निगरानी के लिए पांच वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को स्पेशल रोल ऑब्जर्वर (एसआरओ) नियुक्त किया है। जिन अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, उनमें रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव कुमार रवि कांत सिंह को प्रेसिडेंसी संभाग के लिए एसआरओ बनाया गया है, जबकि गृह मंत्रालय के नीरज कुमार बांसोद को मेदिनीपुर संभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के कृष्ण कुमार निराला बर्दवान संभाग के लिए एसआरओ होंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस के एक अधिकारी ने बताया कि एसआरओ की नियुक्ति से सभी संभागों में एसआईआर प्रक्रिया की जांच मजबूत होगी।

एसआईआर की अंतिम तिथि 11 दिसंबर

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भारत के 12 राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश (अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्यप्रदेश, पुदुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडू, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल) में मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य को पूरा करने के लिए अंतिम तिथि 11 दिसंबर 2025 निर्धारित है। कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ की वेबसाइट सीईओ छत्तीसगढ़ में 12 राज्यों की 2003 की मतदाता सूची उपलब्ध है। जिसमें हमें राज्य, जिला, विधानसभा, मतदान केन्द्र का नाम क्लिक कर हम अपने मतदाता सूची 2003 के रिकार्ड डाउनलोड कर एसआईआर के काम को पूरा कर सकते हैं।

12 नक्सलियों के सरेंडर पर बोले सीएम- अंतिम सांसें गिन रहा नक्सलवाद

श्रीकंचनपथ न्यूज

राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से नक्सलवाद के विरुद्ध सुरक्षाबलों की कार्रवाई में एक बड़ी सफलता हाथ लगी। 12 नक्सलियों ने मुख्यधारा में लौटकर सुरक्षाबलों के समक्ष अपने हथियार डाल दिए। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस आत्मसमर्पण को नक्सलवाद के विरुद्ध जारी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा निर्धारित लक्ष्य—31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद का पूर्ण उन्मूलन—की दिशा में छत्तीसगढ़ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद की कमर टूट चुकी है और यह अब अंतिम सांसें गिन रहा है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पिछले दो वर्षों में सुरक्षा बलों ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। 500 से अधिक माओवादी मुठभेड़ों में न्यूट्रलाइज हुए, जबकि 4,000 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण या गिरफ्तारी दी, जो नक्सलवाद के कमजोर पड़ने का स्पष्ट संकेत है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों के पराक्रम से बस्तर में दशकों से जमी हिंसा के विरुद्ध निर्णायक बढ़त मिली है। उन्होंने राज्य सरकार की नई पुनर्वास नीति की भी विस्तृत जानकारी दी। इसके तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए 15,000 प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति, 3 वर्षों तक 10,000 रुपये मासिक वित्तीय सहायता, कौशल विकास प्रशिक्षण और रोजगार-संबंधी कार्यक्रम शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोलीबारी की भाषा छोड़कर मुख्यधारा से जुड़ना अब बस्तर में हकीकत बन रहा है। पंडुम कैफ़े जैसे नवाचार आज सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक हैं।

बीएसपी प्लांट में महिला ठेका श्रमिक की मौत : 4 दिन पहले सिर पर गिरा था लोहे का पाइप, प्रबंधन पर एफआईआर

भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र के ओएचपी परिसर में 5 दिसंबर को काम करने के दौरान हादसे में महिला श्रमिक की मौत हो गई। घटना सुबह करीब 10.30 बजे वागन टिपलर नंबर 4 के नीचे हुई। मृतका की पहचान पुष्पा साहू (41) निवासी ग्राम रिसामा के रूप में हुई है। पुलिस ने अब इस मामले में बीएसपी प्रबंधन की लापरवाही मानते हुए बीएसपी प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है।

पुलिस की जांच में सामने आया कि, महिला वागन टिपलर नंबर-4 के नीचे सफाई का काम कर रही थी। इस दौरान तेज आवाज के साथ लोहे पाइप सीधे पुष्पा साहू के सिर पर गिरा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत उन्हें मेन मेडिकल पोस्ट पहुंचाया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें

सेक्टर-9 अस्पताल रेफर किया गया। सेक्टर-9 अस्पताल के डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। थाना भिलाई भट्टी में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक भारत सिंह चौधरी ने मर्ग क्रमांक 43/2025 धारा 194 बीएनएसएस के तहत मामले की जांच की। जांच में पाया गया कि, घटना स्थल पर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया था। थाना भिलाई भट्टी पुलिस ने इस मामले में बीएनएस की धारा 106 और 289 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।

सांसद बृजमोहन ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हवाई रूट बढ़ाने का दिया सुझाव

रायपुर। दिल्ली में हुई प्राक्कलन समिति की महत्वपूर्ण बैठक में छत्तीसगढ़ से सांसद और बीजेपी के सीनियर नेता बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य की हवाई सेवाओं के व्यापक विस्तार पर जोर देते हुए कई बड़े सुझाव रखे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और यहां ग्रीन एनर्जी आधारित एयरपोर्ट की जरूरत है।

उन्होंने रायपुर-नवा रायपुर-भिलाई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को ध्यान में रखते हुए एक बड़े ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट को शीघ्र मंजूरी दिए जाने की मांग की। सांसद ने तर्क दिया कि छत्तीसगढ़ आज राष्ट्रीय स्टील और पावर हब के रूप में अपनी पहचान बना चुका है, ऐसे में राज्य में दूसरा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट आर्थिक गति को कई गुना बढ़ा देगा। सांसद अग्रवाल ने बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर और जगदलपुर को प्लेटफॉर्म मिलने को सकारात्मक कदम करार दिया, लेकिन उन्होंने आग्रह किया कि ध्रह 2025-35 के अगले चरण में छत्तीसगढ़ को अतिरिक्त रूट्स और बेहतर एयर सर्विस का लाभ मिले। उन्होंने इन शहरों के लिए नई हवाई मार्ग, उच्च स्तरीय सुविधाएं और बेहतर कनेक्टिविटी अनिवार्य किए जाने की मांग रखी। सांसद ने मंत्रालय की ओर से देश के 87 एयरपोर्ट्स को 100 प्रतिशत ग्रीन एनर्जी में बदलने की उपलब्धि की सराहना की। साथ ही रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर एयरपोर्ट को भी इस सूची में प्राथमिकता से शामिल करने और इसके लिए निश्चित टाइमलाइन घोषित करने की मांग की। उन्होंने रायपुर एयरपोर्ट में डेडिकेटेड सोलर पावर प्लांट स्थापित करने का भी ठोस प्रस्ताव रखा।

छत्तीसगढ़ का कला का नईदिल्ली में सम्मान

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ की कला का देश की राजधानी नईदिल्ली में सम्मान हुआ। नईदिल्ली के विज्ञान भवन में छत्तीसगढ़ की शिल्पकार हीराबाई झरेका बघेल को आज धातुकला में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया।

पत्नी ने पति को जिंदा जलाया, विवाद के बाद पेट्रोल-डालकर लगाई आग

रायपुर। राजधानी रायपुर में एक पत्नी ने अपनी पति को जिंदा जलाकर मार डाला। सोमवार की रात पति-पत्नी के बीच घरेलू विवाद हुआ, जिसके बाद गुस्से में पत्नी ने पति पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी और दरवाजा बंद कर भाग गई। आग में गंभीर रूप से झुलसे पति की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मामला डीडी नगर थाना क्षेत्र का है।

डीडी नगर पुलिस के मुताबिक, डीडी नगर निवासी अरुण पटवा (45 साल) 8 दिसंबर को भतीजी की शादी में शामिल होकर देर रात घर लौटा था। इसी दौरान पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर फिर विवाद शुरू हो गया। परिजनों के अनुसार, अरुण सोने चला गया, तभी पत्नी ने उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और दरवाजा बाहर से बंद कर भाग गई। आग में झुलसे अरुण ने शोर मचाया तो पड़ोसी पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। 70 प्रतिशत जल चुके घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि महिला ने पहले भी दबाव बनाकर परिवार को परेशान किया था। पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।

छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी ने इंडिगो को भेजा नोटिस, 9000 करोड़ रुपए जुर्माने की मांग

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने इंडिगो को कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में मांग की गई है कि पीड़ित यात्रियों को इंडिगो टिकट कीमत का 10 गुना मुआवजा दे। इस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री को भी शिकायत भेजी गई है, जिसमें इंडिगो पर 9000 करोड़ (करीब एक बिलियन डॉलर) का जुर्माना लगाने की मांग की गई है। इधर मंगलवार सुबह 9 बजे रायपुर से मुंबई जाने वाली फ्लाइट कैंसिल हो गई है। इसके अलावा मुंबई, दिल्ली और

हैदराबाद से आने वाली एक-एक फ्लाइट यानी कुल चार फ्लाइट कैंसिल है। दिनभर में और भी फ्लाइटें कैंसिल, डायवर्ट और डिले हो सकती हैं। फ्लाइट संकट से ट्रेनों और बसों में भीड़ बढ़ गई है।

सिविल सोसायटी के संयोजक डॉ. कुलदीप सोलंकी ने इंडिगो के सीईओ को लीगल नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि पांच दिनों में तीन हजार से अधिक फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। सोसायटी ने कहा है कि इंडिगो ने बिना पूर्व सूचना, बिना पारदर्शी कारण बताए फ्लाइटें रद्द कीं। इसके एवज में हर यात्री को टिकट कीमत का कम से कम 10 गुना मुआवजा देने की मांग इंडिगो से की है। सोसायटी ने बताया कि प्रभावित यात्रियों की ओर से केंद्र सरकार को भी शिकायत भेज दी गई है। सोसायटी ने चेतावनी दी है कि यदि 5 दिनों में जवाब नहीं मिला तो सक्षम न्यायालयों और प्राधिकरणों में सिविल और आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

वंदेमातरम् ही क्यों, जन-गण-मन भी आधा अधूरा

पीएम मोदी ने लोकसभा में वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने पर कहा कि कांग्रेस ने इस गीत के दो टुकड़े कर दिए। वंदे मातरम् अंग्रेजों को करारा जवाब था। महात्मा गांधी को भी यह पसंद था। उन्हें इस गीत में नेशनल एंथम दिखता था। फिर वो कौन सी ताकत थी, जिसकी इच्छा पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ी। दरअसल, वंदेमातरम् ही क्यों, जन-गण-मन का भी एक टुकड़ा ही गाया जाता है। जन-गण-मन का पूरा गीत 5 पद या छंदों का है। राष्ट्रगान के रूप में केवल पहला और दूसरा पद ही गाया जाता है, जिसकी अवधि लगभग 52 सेकंड होती है। जन-गण-मन का जितना भी हिस्सा गाया जाता है, उसे भी कई लोग गलत सलत गाते हैं। द्राविड़ उत्कल बंग की जगह द्राविड़ उच्छल बंग गाने वालों की कमी नहीं है। उच्छल जलधि तरंग की जगह उत्कल जलधि तरंग गाने वाले भी मिल जाएंगे। इसी तरह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रचित वंदेमातरम भी मूल रूप से 6 छंदों (पदों) का गीत है, लेकिन भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में संविधान सभा ने इसके केवल पहले दो छंदों को गाने की सहमति दी थी। शुरुआती दो पद (मुखड़ा) संस्कृत में हैं और बाकी के पद बांग्ला (या बांग्ला-संस्कृत मिश्रित) भाषा में हैं, जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था और बाद में कवि गुरू रवींद्रनाथ ठाकुर ने इसे संगीतबद्ध किया। ठाकुर ने ही इस गीत को सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में गाया भी था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस गीत को अपने उपन्यास आनंदमठ में शामिल किया जिससे यह संन्यासी विद्रोह का प्रतीक बन गया और लोगों की जुबान पर आ गया। इस बात पर बहस की जा सकती है कि इन दोनों गीतों को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के नाम पर काटछांट कर क्यों स्वीकार किया गया। यदि आप वंदेमातरम् को पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आप हकला जाएं। जन-गण-मन को भी पूरा याद करना अधिकांश लोगों को मुश्किल लग सकता है। इन गीतों को राजनीति के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। वैसे भी ये दोनों गीत बंगालियों के लिखे हुए हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि शेष देश में एक भी ऐसा कवि या गीतकार नहीं था जिसकी रचना को यह सम्मान दिया जा सके। दरअसल, उस कालखण्ड में ये बातें गौण थीं। राष्ट्रचिन्ह के लिए अशोक चक्र और सिंहों को चुना गया। एक राष्ट्र गीत और एक राष्ट्र गान को अंगीकार किया गया। तब देश के सामने और भी जरूरी मुद्दे थे। आज जब देश सभी मामलों में आत्मनिर्भरता के स्तर को छू चुका है तो इन पुरानी बातों पर बहस क्यों? नेहरू-गांधी-जिन्ना 1940-50 के दशक के नेता थे। स्थान-काल और परिस्थितियां अलग थीं। तब जिसपर सिर खपाना जरूरी नहीं लगा होगा, वह आज महत्वपूर्ण हो गया होगा। अगर सुधारना जरूरी लगे तो सुधार लेना चाहिए। बल्कि नए सिरे से गीत लिख लेने चाहिए।

संपादकीय

वंदे मातरम का उद्घोष

राष्ट्रीय एकता जगाने का गान बने

यह सुखद ही है कि कृतज्ञ राष्ट्र देश के स्वतंत्रता सेनानियों में ओज का संचरण करने वाले गीत वंदे मातरम के सृजन के डेढ़ सौ साल पूरे होने को एक उत्सव की तरह मना रहा है। स्वतंत्रता के लिये संघर्षरत करोड़ों भारतीयों में इस गीत ने आजादी का जज्बा भरा था। लाखों स्वतंत्रता सेनानी इस गीत से प्रेरित होकर स्वतंत्रता संग्राम में सर्वस्व अर्पित करने को तत्पर हो जाते थे। इस पावन वेला में देश के विभिन्न भागों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सही मायनों में यह अवसर राष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करने का भी है। इस गीत की सर्वस्वीकार्यता का आलम ये था कि भारत आने से पहले दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान की दृष्टि से देखा था। इसी आलोक में वंदे मातरम के डेढ़ सौ साल पूरे होने पर लोकसभा में इस पर चर्चा का शुरू होना सुखद ही है। संसद में प्रधानमंत्री ने कहा भी कि जब इस गीत के सृजन के पचास साल पूरे हुए तो देश परतंत्र था। जब इसके सौ साल पूरे हुए तो देश आपातकाल के दौर से गुजर रहा था, फ्लत: उस दौर में इस गीत को जनता व स्वतंत्रता सेनानियों का सकारात्मक प्रतिसाद नहीं मिला। निस्संदेह,बंकिम चंद्र चटर्जी की इस रचना ने बंगाल में क्रांतिकारियों को गहरे तक प्रेरित किया और स्वतंत्रता संग्राम को गति देने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। हालांकि, विपक्ष इसे सुर्खियों में लाने के फैसले के राजनीतिक निहितार्थों की बात कर रहा है। वे इसके समय को लेकर प्रश्न उठा रहे हैं। अविभाजित बंगाल की पृष्ठभूमि में जन्मे इस ओज के गीत को बंगाली समाज ने अपनी अस्मिता से जोड़कर देखा। खासकर बंगाल विभाजन के बाद इसे बंगाल की अस्मिता पर फिरंगियों के प्रहार के दौर में एक मरहम के तौर पर देखा। निस्संदेह, देश ऐसे स्मरण उत्सव का हकदार है, मगर वे चुनावी नजरियों से मुक्त हों।

> “ इस पावन वेला में देश के विभिन्न भागों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सही मायनों में यह अवसर राष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करने का भी है। इस गीत की सर्वस्वीकार्यता का आलम ये था कि भारत आने से पहले दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान की दृष्टि से देखा था।

विपक्ष की दलील है कि जब पश्चिम बंगाल एक महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है तो इस गीत के प्रसंगवश राजनीतिक लाभ-हानि के तर्क गढ़े जा रहे हैं। संसद में प्रधानमंत्री के संबोधन में वंदे मातरम को एकता के सूत्रधार के रूप में सराहा गया। लेकिन इसके राजनीतिक निहितार्थों पर भी चर्चा हुई। दरअसल, उन्होंने जब भी कांग्रेस की आजादी से पहले और बाद की नीतियों को कटघरे में खड़ा किया या फिर ऐतिहासिक विवादों का नये सिरे से जिक्र किया, तो विपक्ष ने उसे निशाने पर लिया। विपक्षी दलील है कि राष्ट्रीय गीत का सम्मान करने की कवायद में वैचारिक विभाजन को हवा दी जा रही है। कहा गया कि पश्चिम बंगाल, जहां इस गीत का जन्म हुआ, वहां की सांस्कृतिक पहचान राजनीति से जुड़ी रही है। वंदे मातरम एक भावनात्मक प्रतीक है और इसीलिए एक रणनीतिक प्रतीक भी। दरअसल, विपक्ष की नाराजगी राजग सरकार की उस प्रवृत्ति को लेकर है जिसमें वह सांस्कृतिक प्रतीकों को राजनीतिक अखाड़े में बदल रही है। उन्हें आशंका है कि साझी विरासत पर चिंतन के लिये आयोजित विमर्श का उपयोग चुनावी लाभ अर्जित करने के लिये किए जाने का खतरा है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अपनी जड़ें जमाए हुए है, फिर भी उसे सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है।

संसद में राष्ट्रीय गीत पर चर्चा का ममता बनर्जी द्वारा समर्थन किया जाना दर्शाता है कि वह इस मुद्दे को छोड़ने का इरादा नहीं रखती हैं। विडंबना ही है कि लाखों स्वतंत्रता सेनानियों में ओज भरने वाले गीत के विमर्श में चिंतन की गंभीरता प्रभावित हुई है। निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल आज बेरोजगारी, पलायन और राजनीतिक हिंसा से जूझ रहा है। इसमें दो राय नहीं कि हमारा सांस्कृतिक गौरव आवश्यक है, लेकिन यह सुशासन का विकल्प नहीं हो सकता। इस ओज के गीत के 150 साल पूरे होने पर, इसे एकता को मजबूत करने और राष्ट्रवाद को बहुलता से स्वीकार करने के अवसर के रूप में होना चाहिए था। लेकिन इसके बजाय, इस बहस के ध्रुवीकृत माहौल में बदलने के विवाद के पैदा होने की चिंता है। सही मायनों में देश के नेतृत्व का इतिहास का उपयोग राष्ट्र को एकजुट करने वाला होना चाहिए।

केंद्र सरकार ने 'संचार साथी' ऐप हर स्मार्ट फोन में प्री इंस्टाल कराने का आदेश वापस ले लिया है। जितने सहज तरीके से सरकार इस मामले में पीछे हटी है वह मामूली नहीं है। यह हैरान करने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की ओर से इस मामले में कोई प्रतिरोध ही नहीं किया गया। पहले दिन एक आदेश जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि तीन महीने में हर स्मार्ट फोन में 'संचार साथी' ऐप इंस्टाल होकर आएगा और पुराने फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट करने पर यह इंस्टाल हो जाएगा। कहा गया कि यह ऐप फोन चोरी हो जाने पर उसे खोजने में मदद करेगा और साइबर फॉड से बचाएगा।

सरकारी ऐप्स की सुरक्षा भगवान भरोसे

अजीत द्विवेदी

जब इसका विरोध हुआ तो एक दिन दूरसंचार मंत्री ने कहा कि इस ऐप को डिलीट करने का विकल्प यूजर्स के पास होगा। इसके बाद भी विरोध जारी रहा तो अगले दिन संचार विभाग ने कहा कि यह ऐप प्री इंस्टाल नहीं होगा। लोग चाहें तो इसे डाउनलोड करके इंस्टाल कर सकते हैं। सवाल है कि क्या सरकार को नहीं पता था कि अगर किसी ऐप को हर स्मार्टफोन में अनिवार्य करने का आदेश दिया जाएगा तो उसका विरोध होगा? सरकार को निश्चित रूप से पता था। उसको यह भी पता था कि विपक्ष भारत को सर्विलेंस स्टेट बनाने के आरोप लगाएगा। फिर भी सरकार की ओर से यह आदेश जारी किया गया। इसका अर्थ है कि सरकार लोगों को आजमा रही थी। विपक्ष को भी आजमा रही थी। सरकार यह देखने का प्रयास कर रही थी कि ऐसे किसी कदम का कितना विरोध हो सकता है। ऐसा मानने का कारण यह है कि अगर सरकार इस आदेश को लेकर गंभीर होती तो इतनी आसानी से पीछे नहीं हटती। दूसरा कारण यह है कि संचार विभाग की ओर से जो तर्क दिया गया है वह बहुत लचर है। संचार विभाग ने कहा है कि डेढ़ करोड़ लोगों ने इसे डाउनलोड कर लिया है, इसका अर्थ है कि इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है इसलिए इसको अनिवार्य करने का फैसला वापस लिया जा रहा है।

सोचें, कहां तो सौ करोड़ स्मार्टफोन्स में ऐप प्री इंस्टाल कराना था और कहां डेढ़ करोड़ डाउनलोड पर सरकार संतुष्ट हो गई? उस डेढ़ करोड़ डाउनलोड में भी कितना ऐप एक्टिवेट होगा और कितना डिएक्टिवेट रहेगा यह पता नहीं है। तभी लग रहा है कि 'संचार साथी' ऐप को लेकर दिया गया आदेश तदर्थ था और एक प्रयोग था, यह इससे भी साबित होता है कि इस बारे में कोई तकनीकी जानकारी नहीं दी गई। ध्यान रहे इस ऐप का जो दायरा है उससे साफ था कि सिम लेने के लिए इस्तेमाल की गई आईडी के साथ साथ मोबाइल नंबर, यूजर की लोकेशन, डिवाइस की पहचान यानी आईएमईआई का डाटा सरकार के पास रहेगा।

लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि डाटा कितने समय तक और कहां सुरक्षित रखा जाएगा। ऐप का सोर्स कोड पता नहीं है और न स्टोरेज को सुरक्षित रखने के लिए किस स्तर का इनक्रिप्शन हो रहा है यह स्पष्ट है। इसकी निगरानी किसके पास होगी और कौन कौन एजेंसी या लोग इसके डाटा को एक्सेस कर पाएंगे यह भी नहीं बताया गया है। यह डाटा किसी थर्ड पार्टी को उपलब्ध हो सकता है या इसका कारोबारी इस्तेमाल हो सकता है, इस बारे में भी स्पष्टता नहीं है। अगर सरकार गंभीर होती तो इन सबके बारे में पहले से बताया जाता।

सरकार को यह भी पता था कि अगर यह आदेश लागू किया गया तो कानूनी रूप से इसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा। ध्यान रहे सुप्रीम कोर्ट ने पुत्तुस्वामी केस में 2017 में निजता को लेकर एक अहम फैसला सुनाया था। इसमें सर्वोच्च अदालत ने लीगलिटी यानी वैधता, नीड यानी आवश्यकता और प्रोपोर्शनलिटी यानी अनुपात के तीन पैमाने तय किए थे। निजता के मामले में सरकार के हर आदेश को इन तीन कसौटियों पर कसने की जरुरत है। जहां तक वैधता की बात है तो सरकार संसद से कानून बनाने का रास्ता नहीं ले रही थी। वह सीधे एक कार्यकारी आदेश से इसे 'संचार साथी' ऐप को हर फोन में इंस्टाल करना चाह रही थी। आवश्यकता की जहां तक बात है तो इसे अनिवार्य करने का आदेश देकर सरकार अपनी कमजोरी जाहिर कर दी। सरकार का आदेश यह साबित कर रहा था कि ऐसे किसी कदम के बिना वह साइबर सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पाएगी। जहां तक अनुपात की बात है तो वह सबको दिख रहा है कि सरकार इससे जितनी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी उससे ज्यादा खतरा बढ़ा देगी। सो, तीनों कसौटियों पर सरकार का आदेश खारिज हो जाता।

ऐसा लग रहा है कि सरकार यह देखना चाहती थी कि किसी आपदा में कितना अवसर बन सकता है। ध्यान रहे साइबर फ्रॉड एक आपदा की तरह है। हर दिन कहीं न कहीं किसी को डिजिटल अरेस्ट करके ठगी करने का मामला सामने आ रहा है या क्रेडिट व डेबिट कार्ड का डाटा चुरा कर खातों से पैसे निकाल लेने की खबरें आ रही हैं। हजारों करोड़ रुपए साइबर फ्रॉड के जरिए हर साल लूटे जा रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि सरकार ने साइबर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए बगैर डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा दिया। और जब साइबर क्राइम महामारी बन गया तो उसे रोकने के बहाने 'संचार साथी' ऐप लेकर आ गई! याद करें कैसे कोरोना की महामारी के समय केंद्र सरकार ने 'आरोग्य सेतु' ऐप को अनिवार्य करने का प्रयास किया था। उस समय भी इसका भारी विरोध हुआ तो सरकार पीछे हटी। 'संचार साथी' ऐप के मामले में भी सरकार पीछे हट गई है। लेकिन ऐसा लग रहा है लोगों की जानकारी जुटाने के काम से सरकार पीछे नहीं हटी है। 'केवाईसी' की मजबूरी भी एक महामारी की तरह लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है।

ध्यान रहे स्मार्टफोन में बहुत सारे ऐप बाई डिफॉल्ट इंस्टाल होते हैं। लेकिन लोगों के पास उन्हें डिलीट करने का विकल्प होता है। जिस ऐप को डिलीट करने का विकल्प नहीं दिया जाता है उसका पूरी दुनिया में विरोध होता है। जैसे गूगल के स्मार्टफोन में इंटरनेट ब्राउजर के तौर पर क्रोम के इंस्टाल होने का होता है। सरकार को यह पता है कि इस तरह से हर फोन में कोई ऐप अनिवार्य रूप से इंस्टाल करने के क्या खतरे हैं और क्या चुनौतियां हैं। फिर भी सरकार ने इसकी पहल की। तभी ऐसा लग रहा है कि सरकार लोगों के प्रतिरोध को आजमाना चाहती थी। वह ठहरे हुए पानी में कंकड़ फेंक कर यह देखना चाहती थी कि कितनी लहर उठती है। जब लहर ऊंची उठी तो सरकार एक एक कदम करके पीछे हट गई, उसने यू टर्न ले लिया। लेकिन तय मानें कि यह प्रयोग समाप्त नहीं हुआ है।

करोड़ों लोग जो स्वेच्छा से इसे डाउनलोड करके इंस्टाल करेंगे, उनके फोन में प्रायोगिक तौर पर इसका इस्तेमाल होगा। इस ऐप को जिस तरह के एक्सेस देने की बात है उससे लग रहा है कि यह व्यक्ति के हर कदम की निगरानी कर सकता है। उसे कैमरे से लेकर लाइब्रेरी यानी स्टोरेज और माइक से लेकर कॉल और मैसेज लॉग तक का एक्सेस देना होगा। इसका मतलब है कि ऐप न सिर्फ यूजर की लोकेशन बता सकता है, बल्कि फोन सुन सकता है, सारे मैसेज पढ़ सकता है, स्टोरेज में रखे फोटो, वीडियो देख सकता है और फोन रखने वाले के फिटनेस व उसकी सेहत से जुड़े सारे आंकड़े भी देख सकता है। सोचें, यह किसी भी व्यक्ति की निजता और उसकी सुरक्षा के लिए कितनी बड़ी चुनौती है!

यह सिर्फ निजता के लिए खतरा नहीं पैदा कर रहा है, बल्कि हर व्यक्ति को एक साथ साइबर अटैक का शिकार बनने के खतरे में भी डालता है। अगर एक सरकारी ऐप करोड़ों लोगों के फोन में हो और कोई हैकर उसी ऐप को टारगेट करके अटैक करे तो एक साथ कितने लोगों का नुकसान कर सकता है? एक साथ करोड़ों फोन हैक किए जा सकते हैं। एक साथ करोड़ों लोगों के निजी व वित्तीय डाटा चुरा कर उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। लाखों लोगों को ब्लैकमेल किया जा सकता है। ऐसे अनगिनत खतरे हैं, जिनकी संभावना साफ दिख रही है। यह खतरा ज्यादा इसलिए है क्योंकि सरकारी ऐप्स की सुरक्षा भगवान भरोसे होती है।

कामकाजी संस्कृति को मानवीय बनाने की पहल

डॉ. जगदीप सिंह

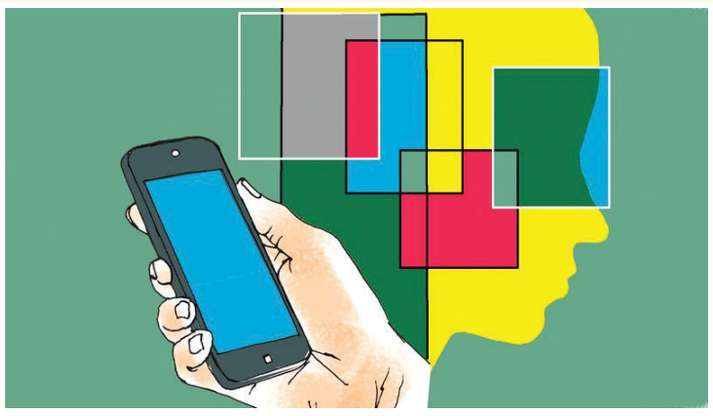

सुप्रिया सुले का यह विधेयक अगर स्थायी समिति को भेजा जाता है तो उसके पास मौका होगा कि वह भारत के कामकाजी संस्कृति को वाकई मानवीय बनाए। यह नींद, परिवार, स्वास्थ्य और सम्मान की बात है।लोकसभा के शीतकालीन सत्र में बारामती की सांसद सुप्रिया सुले ने 'द राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025' पेश किया। पहली बार कोई विधेयक उनके अपने 24म7 बजते फोन को चुप कराने की बात कर रहा था। यह निजी सदस्य विधेयक कर्मचारियों, अधिकारियों और विधायकों-सांसदों को कार्य-समय के बाहर फोन कॉल, ई-मेल या किसी भी काम से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक संचार का जवाब देने से कानूनी रूप से पूरी तरह मुक्त करता है। यह प्रस्ताव करोड़ों थके-हारे कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों की चैन की नींद के लिए आवाज़ है।

विधेयक के प्रमुख प्रावधानों में उल्लेख है कि कार्य-समय के बाद अवकाश के दौरान नियोक्ता कर्मचारी से काम का संचार करने का दबाव नहीं डाल सकेगा। उल्लंघन पर संगठन के कुल वार्षिक वेतन बिल का एक प्रतिशत तक जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। एक नई 'एम्प्लॉयी वेलफेयर अथॉरिटी' प्रावधान होगा, जो डिस्कनेक्ट पॉलिसी लागू करवाएगी, डिजिटल डिटॉक्स सेंटर चलाएगी और काउंसलिंग मुहैया कराएगी। हर कंपनी को साल में कम से कम एक बार अपनी डिस्कनेक्ट पॉलिसी की समीक्षा करनी होगी। साथ ही, कर्मचारी यूनियन या प्रतिनिधियों से लिखित सहमति लेनी होगी।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की 2024 रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय औसतन 2,277 घंटे सालाना काम करते हैं—जापान से 600 घंटे और जर्मनी से 900 घंटे अधिक। नैसकॉम के सर्वे में 62 प्रतिशत आईटी कर्मचारियों ने माना कि उन्हें रात दस बजे के बाद भी काम के मैसेज आते हैं। सीईडीए-सीएमआईई के आंकड़े बताते हैं कि बर्नआउट की वजह से हर साल 46 प्रतिशत युवा कर्मचारी नौकरी छोड़ रहे हैं। एक आरटीआई जवाब में खुलासा हुआ कि 2020-2024 के बीच केंद्रीय सचिवालय के अठारह कर्मचारियों ने अत्यधिक कार्य-दबाव के कारण आत्महत्या की।

सांसदों-विधायकों की स्थिति भी दयनीय है। एक सांसद के फोन में औसतन 300-400 वॉट्सएप ग्रुप होते हैं। रात दो बजे भी कोई मरीज अस्पताल में भर्ती कराने की गुहार लगा दे तो जवाब देना 'राजनीतिक मजबूरी' बन जाता है। सुप्रिया सुले ने स्वयं स्वीकार किया कि वे रात में फोन साइलेंट नहीं कर पातीं।

सुप्रिया सुले का यह दूसरा प्रयास है। वर्ष 2019 में भी उन्होंने विधेयक पेश किया था, लेकिन आगे नहीं बढ़ सका। वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार ने चार नए श्रम संहिता लागू किए, लेकिन उनमें 'राइट टू डिस्कनेक्ट' का कोई उल्लेख नहीं है। उल्टे ओवरटाइम की सीमा बढ़ा दी गई। इसी सत्र में शशि थरूर, मनीष तिवारी और कनिमोझी ने भी काम के घंटे और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विधेयक पेश किए हैं। वर्ष 2024 में केरल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 'शाम छह बजे के बाद नो वॉट्सएप' का सर्कुलर जारी किया था, पर अफसरों के विरोध के कारण उसे वापस लेना पड़ा। तेलंगाना और कर्नाटक के आईटी हब और कुछ स्टार्टअप्स ने स्वेच्छा से 'इवनिंग डिस्कनेक्ट पॉलिसी' शुरू की है। भारत की 92 प्रतिशत श्रमशक्ति असंगठित क्षेत्र और छोटे-मध्यम उद्योगों में है, वहां न्यूनतम मजदूरी भी मुश्किल से मिलती है। यहां तो डिस्कनेक्ट का सवाल ही नहीं उठता।

फ्रांस ने वर्ष 2017 में सबसे सख्त कानून बनाया और 50 से अधिक कर्मचारियों वाली हर कंपनी को डिस्कनेक्ट पॉलिसी अनिवार्य की। बेल्जियम, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, आयरलैंड और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया (2024) ने भी इसे कानूनी अधिकार बना दिया। इन देशों से तीन बड़ी सीखें हैं। पहली, कानून से ज़्यादा प्रवर्तन तंत्र मायने रखता है। दूसरी, छोटे उद्यमों को शुरुआती छूट और ट्रेनिंग ज़रूरी है। तीसरी, जुर्माना कंपनी के टर्नओवर से जोड़ा जाए ताकि छोटी कंपनियां दिवालिया न हो जाएं।ऑस्ट्रेलिया ने यही किया।

भारत के लिए आगे तीन रास्ते संभव हैं। पहला, इस विधेयक को सरकारी विधेयक बनाकर श्रम संहिता-2020 में संशोधन के रूप में लाया जाए। दूसरा, शुरुआत में इसे सरकारी क्षेत्र और 250 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों पर ही लागू किया जाए। तीसरा, फ्रांस की तर्ज पर हर कंपनी को अपना 'डिस्कनेक्ट चार्टर' बनाने को बाध्य किया जाए, जिसमें कर्मचारी प्रतिनिधि भी शामिल हों।

सुप्रिया सुले का यह विधेयक अगर स्थायी समिति को भेजा जाता है तो उसके पास मौका होगा कि वह भारत के कामकाजी संस्कृति को वाकई मानवीय बनाए। यह नींद, परिवार, स्वास्थ्य और सम्मान की बात है। इंसान को यह अधिकार तो मिलना ही चाहिए कि वह रात में चैन की नींद सो सके। अगर यह कोशिश कानून बन गई तो भारत की करोड़ों थकी आंखों के लिए यह सबसे बड़ा तोहफा होगा।

लेखक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं।

भारत की जमीन पर चीन का दावा

हरिशंकर व्यास

पिछले दिनों दुनिया ने देखा और सुना कि ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय मूल की एक महिला को किस तरह शंघाई हवाईअड्डे पर 18 घंटे तक रोक रखा गया और उसके भारतीय पासपोर्ट को अवैध बताया गया। कारण क्या था? कारण यह था कि पासपोर्ट पर उस महिला का जन्मस्थान अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ था। चीन ने उस महिला से कहा कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है इसलिए वहां जन्मी किसी व्यक्ति का पासपोर्ट भारत नहीं जारी कर सकता है। उस महिला को बुरी तरह से परेशान किया गया। उसे पानी खरीदने तक से रोका गया। उसकी फ्लाइट छूट गई तो दूसरी फ्लाइट की टिकट खरीदने से रोका गया। बाद में किसी तरह उसने ब्रिटेन में भारतीय दूतावास से संपर्क किया तो उसको वहां से निकाला जा सका। लेकिन उसके अगले दिन चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने भारत के अभिन्न अंग अरुणाचल प्रदेश को जांगनान बताते हुए कहा कि यह चीन का हिस्सा है और चीन इस पर भारत के कब्जे को मान्यता नहीं देता।

चीन पहले भी इस तरह का दावा कर चुका है। इतना ही नहीं आए दिन चीन की सरकार अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के नाम बदलती रहती है। कभी अरुणाचल के किसी पहाड़ का तिब्बती नाम रख दिया जाता है तो कभी किसी नदी का नाम बदल दिया जाता है तो कभी किसी कस्बे का नाम बदल दिया जाता है। चीन अब तक दर्जनों नदियों, पहाड़ों, कस्बों और गांवों के नाम बदल चुका है। जब भी वह ऐसा करता है तो भारत की ओर से एक लाइन की प्रतिक्रिया दी जाती है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और चीन के दावा करने से अरुणाचल उसका नहीं हो जाएगा।

सोचें, चीन इसी तरह के दावे करते करते हुए पूर्वी लद्दाख के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका है। भारत की ओर से भले कहा जाएगा कि कोई भारतीय सीमा में नहीं घुसा है लेकिन हकीकत है कि चीन ने जून 2020 में गलवान घाटी में झड़प के बाद उस इलाके में भूगोल बदल चुका है। भारत की सेना पहले जहां तक गश्त करती थ, कई जगह वह इलाका बफर जोन में बदल चुका है। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश में चीन लंबे समय से अपने पैर फैला रहा है और भाजपा के सांसद व प्रदेश अध्यक्ष रहे तापिर गाओ ने संसद में खड़े होकर कहा कि भारत की सीमा में 50 किलोमीटर से ज्यादा अंदर चीन के सैनिक घुसे हुए हैं। उन्होंने सड़कें और पुल बनाए हैं। डोकलाम में जो हुआ वह भी पूरे देश ने देखा।

क्या इन सबके बावजूद भारत ने कभी चीन के साथ ऐसा कुछ करने का प्रयास किया? भारत के नेताओं के मुंह से चीन का नाम तक नहीं निकलता है। जब चीन अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों के नाम बदलता है उसी समय क्या भारत की ओर से अक्साई चिन के उस हिस्से की मांग चीन से नहीं करनी चाहिए, जो पाकिस्तान ने उसे सौंप दी है? अक्साई चिन ऐतिहासिक रूप से भारत का हिस्सा है। लेकिन भारत उस पर दावा नहीं करता है। पीओके लेने की बात कही जाती है तो यह नहीं कहा जाता है कि चीन के कब्जे वाला इलाका भी लेंगे। भारत की ओर से कभी तिब्बत के समर्थन में एक शब्द नहीं निकलता है, जिसे पिछले सदी के पांचवे दशक में चीन ने कब्जा लिया। चार हजार किलोमीटर की लंबी सीमा तिब्बत की थी और वह भारत के लिए बफर का काम करता था। लेकिन भारत तिब्बतियों के अधिकार के समर्थन में नहीं खड़ा होता है। यहां तक कि ताइवान पर चीन के आक्रमणकारी बरताव पर भी भारत खामोश रहता है।

उलटे भारत की ओर से लगातार चीन के साथ कारोबार बढ़ाया जा रहा है। भारत अपनी रोजमर्रा की जरुरतों से लेकर तकनीकी, कृषि व ऑटोमोबाइल जरुरतों के लिए लगभग पूरी तरह से चीन से आयात पर निर्भर हो गया है। अकेले चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा एक सौ अरब डॉलर सालाना की सीमा पार कर गया है। चीन आक्रांत है। वह भारत की जमीन पर दावा करता है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का विरोध करता है। पाकिस्तान की खुलेआम मदद करता है। पिछले ही दिनों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने अपनी तकनीक पाकिस्तान को दी। अमेरिकी संसद को रिपोर्ट देने वाली एक संस्था ने बताया है कि चीन ने अपनी युद्ध तकनीक का लाइव परीक्षण उस युद्ध के दौरान कराया। इसके बावजूद भारत न सिर्फ चीन की ज्यादतियों पर चुप रहता है, बल्कि उसके साथ लगातार कारोबार बढ़ाता जा रहा है। भारत के सारे शीर्ष मंत्री पिछले कुछ दिनों में चीन होकर आए हैं। सोचें, कैसी कूटनीति है कि अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया तो उससे व्यापार संधि फाइनल करने की बजाय भारत ने चीन और रूस से दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी और उनके साथ व्यापार बढ़ाने की बातें शुरू कर दीं।

खेल बुनियादी ढांचे पर भी सवाल

अब हरियाणा के खेल बुनियादी ढांचे पर भी सवाल खड़ा होने लगे हैं, जिससे वहां प्रतिभाओं के उदय की जमीन तैयार हुई थी। 48 घंटों के अंदर दो बॉस्केटबॉल खिलाड़ियों की हादसों में मौत की खबर सदमा पहुंचाने वाली है। भारत के खेल मानचित्र पर इस सदी में हरियाणा का शानदार उदय हुआ। वहां से निकले पहलवानों, निशानेबाजों, एवं दूसरे एथलीट ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का गौरव बढ़ा कर देश के अंदर हरियाणा की हैसियत बढ़ाई। जैवेलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा की उपलब्धियां इस कहानी को चरम ऊंचाई तक ले गईं। इन सफलताओं का श्रेय इस सदी के आरंभ से हरियाणा में बने स्पोर्ट्स इन्फ्रास्टक्चर को दिया गया। लेकिन हाल के वर्षों में हरियाणा की प्रतिष्ठा पर आंच आने लगी है। पहले तो वहां से उभरी महिला पहलवानों के यौन शोषण के कथित मामलों ने माहौल खराब किया। अब उस बुनियादी ढांचे पर भी सवाल खड़ा होने लगे हैं, जिससे वहां प्रतिभाओं के उदय की जमीन तैयार हुई। 48 घंटों के अंदर दो बॉस्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत की खबर सदमा पहुंचाने वाली है। रोहतक के करीब लखन माजरा में 16 वर्षीय हार्दिक राठी की मृत्यु बास्केटबॉल कोर्ट में खंभा गिरने से हो गई। दो दिन पहले बहादुरगढ़ के पास 15 वर्षीय अमल की मौत इसी तरह के हादसे में हुई थी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने इल्जाम लगाया है कि लखन माजरा में उपलब्ध धन का उपयोग नहीं किया गया, नतीजतन वहां हुई दुर्घटना सीधे तौर पर सरकारी नाकामी का नतीजा है। यह तो आम समझ है कि ऐसी घटनाएं निरंतर निगरानी और रखरखाव में लापरवाही के कारण ही होती हैं। फिर एक जैसे दो हादसे लगातार हो जाएं, तो उनको लेकर गंभीर सवाल जरूर ही उठाए जाएंगे। हरियाणा सरकार को इन सवालों को गंभीरता से लेना चाहिए। उसे अपने राज्य के खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर का पूरा ऑडिट कराना चाहिए और जहां कमियां पाईं जाएं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त कराना चाहिए। वरना, खेल जगत में हरियाणा का उदय एक अस्थायी परिघटना बन कर रह जाएगी।

ITR फाइल 500/-
Whatsapp पर बनवाएँ
Income Tax फाइल, GST रजिस्ट्रेशन, TDS रिफंड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट
CMA DATA, MSME, BALANCE SHEET, फूड लाइसेंस
हमारे Tax Expert आपकी मदद हेतु तैयार है।
www.onlytds.com
सम्पर्क - शेखर गुप्ता 9300755544 - 8878655544

श्रीकंचनपथ
भिलाई-दुर्ग

प्रिंट और डीजिटल मीडिया में
सभी प्रकार के विज्ञापन
के लिए
संपर्क करें
Mob.-:
9303289950
7987166110

खास खबर

बेलौदी में शिक्षक कमी पर फूटा गुस्सा, सड़क जाम

दुर्ग। जिले के बेलौदी गांव में स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी को लेकर आज मिडिल और प्राइमरी स्कूल के बच्चों के साथ उनके अभिभावकों ने नगपुरा रोड पर चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि वे कई महीनों से संबंधित अधिकारियों को शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शिक्षकों की कमी से बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। जाम के कारण दुर्ग-नगपुरा मार्ग पूरी तरह ठप हो गया और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। प्रिंसिपल ने बताया कि कई शिक्षक बीएलओ ड्यूटी में लगे हुए हैं, जिसके चलते स्कूल में स्टाफ की कमी है।

सहा. प्राध्यापक अमृतेष शुक्ला को पीएचडी की उपाधि

भिलाई। इंदिरा गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वैशाली नगर के सहा. प्राध्यापक अमृतेष शुक्ला को हेमचंद यादव विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। वायवा में बाह्य परीक्षक के रूप में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रो डॉ मधुरेंद्र कुमार उपस्थित रहे। शोध का विषय 'छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2018 में जातिवाद की भूमिका- (दुर्ग जिले के विशेष संदर्भ में)' था। इनके शोध निर्देशक डॉ डी.एन. सूर्यवंशी सेवानिवृत प्राचार्य सुराना महाविद्यालय, दुर्ग थे। शोध केंद्र निर्देशक डॉ प्रमोद यादव विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग,सुराना महाविद्यालय हैं।

25 को भिलाई आएंगे पं. धीरेंद्र शास्त्री, तीसरे दिन दिव्य दरबार

दुर्ग-भिलाई। दुर्ग जिले की ट्विनसिटी भिलाई में पहली बार बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा होने जा रही है। शहर में इस ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन को लेकर लोगों में उत्साह है। श्री हनुमंत कथा 25 से 29 दिसंबर तक जयंती स्टेडियम के पास स्थित विशाल ग्राउंड में होगी। हर दिन दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक पंडित शास्त्री श्रद्धालुओं को कथा सुनाएंगे। 27 दिसंबर को दिव्य दरबार लगेगा। इसमें श्रद्धालुओं की पर्ची निकालकर समस्याओं का समाधान और मार्गदर्शन दिया जाएगा।

रीदत्त मंदिर में प्रकट महोत्सव मनाया गया

दुर्ग। सिंधिया नगर स्थित श्रीदत्त मंदिर के नवनिर्मित परिसर में श्रीदत्त जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। गुरु गुरुदेव प्रकाश कुलकर्णी के मार्गदर्शन में एक विशाल भंडारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उभरते कलाकारों सौमेंन्द्र फडके और चैतन्य जोगलेकर ने श्रीदत्त देवता को समर्पित भक्ति गीतों का अत्यंत मधुर और भक्तिभाव से ओतप्रोत प्रस्तुति दी।

स्वयं पर, विधाता पर और उसके बनाए विधान पर विश्वास ही समर्पणता है - वीणा दीदी

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय द्वारा सेक्टर 7 स्थित पीस ऑडिटोरियम में कर्नाटक हुबली से आई गीता ज्ञान विशेषज्ञा ब्रह्माकुमारी वीणा दीदी ने सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 9 के श्लोक 22

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना: पर्युपासते
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्

के बारे में बताते हुआ कहा कि जो संपूर्ण समर्पण मेरे अनन्य है जो उनको चाहिए वो देगा और उसकी रक्षा भी करेगा। खुद पर विश्वास विधाता पर विश्वास और उसके विधान पर विश्वास ही समर्पण्यता है।

ब्रह्मकुमारी दीदी ने कहा कि अभाव, स्वभाव, प्रभाव, दबाव यह चार बातें हमें आकर्षित करती हैं। यही हमें भटकाती भी हैं।

सूर्य की किरणें बिना किसी से प्रभावित हुए सम्पूर्ण

प्रकृति,धरती,मनुष्यात्माओं सहित ब्रह्मांड को प्रभावित करती है।

दिल की बात दिल तक,दिमाग की बात दिमाग तक पहुंचती है।

इसलिए सच्ची दिल साफ दिल से परमात्मा को याद करे, सच्चे दिल पर साहिब राजी।

वहीं रिसाली मैत्री कुंज प्रभु प्राप्ति भवन में आयोजित ड्राइंग एंड पेंटिंग के सभी प्रतिभागी बच्चों को ब्रह्माकुमारी वीणा दीदी ने पुरस्कृत किया।

इस योग कार्यक्रम और गीता ज्ञान से आंतरिक परिवर्तन कार्यक्रम के लिए भिलाई सेवा केंद्रों की निदेशिका ब्रह्माकुमारी आशा दीदी जी ने वीणा दीदी का सम्मान किया।

डिवाइन ग्रुप के बच्चों द्वारा सुंदर धन्यवाद ज्ञापन नृत्य प्रस्तुत किया गया।

कार्यक्रम का सुंदर संचालन ब्रह्माकुमारी प्राची दीदी ने किया।

डिवाइडर फोड़कर सड़क पार करने वालों से सख्ती से निपटेगा प्रशासन

संयुक्त सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर ने मुख्य सड़कों से मवेशियों को हटाने के दिए निर्देश

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। मुख्य सड़कों पर बंद किये गए कट को फोड़कर वहां से आवाजाही करने वालों से अब प्रशासन सख्ती से पेश आएगा। इसके साथ ही व्यस्त सड़कों पर विचरने वाले मवेशियों को हटाने के लिए भी सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं।

जिले में यातायात नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन और सड़क दुर्घटनाओं पर रोकथाम हेतु आवश्यक व्यवस्था के संबंध में आज कलेक्टोरेट सभा कक्ष में जिला स्तरीय संयुक्त सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई।

कलेक्टर अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल भी शामिल हुए। कलेक्टर सिंह ने कहा कि जिले में यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराने सहित सड़क दुर्घटनाओं को रोकने, प्रभावी उपाय किया जाएं।

कलेक्टर ने एनएचआई के अधिकारियों को नेहरू नगर चौक से अंजोरा तक सड़कों में विचरण करने वाले पशुओं को हटाने की कार्यवाही निरंतर जारी रखने और नेहरू नगर चौक से कुम्हारी टोल प्लाजा तक सर्विस रोड डामरीकरण कराने के निर्देश दिये।

उन्होंने अधिकारियों को एनएचआई के रोड में जहां मिडिल कट बंद किया गया है, उसको तोड़ने वालों पर निगरानी कर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। इसी प्रकार एसडीएम भिलाई को भिलाई नगर के सूर्या मॉल के पास और सुपेला मार्केट के पास पार्किंग ठेकेदार द्वारा सड़क पर वाहन पार्किंग कराने पर वाहन जब्ती करने के कार्यवाही के निर्देश दिये। उन्होंने पशुओं के सड़कों में विचरण करते पाये जाने पर पशुपालकों को पूर्व में जारी बॉण्ड के आधार पर कार्यवाही करने तथा सड़क किनारे के सभी प्रकार के अतिक्रमण को तत्काल हटाने अधिकारियों को निर्देशित किया।

कलेक्टर ने मॉलवाहक वाहनों का उपयोग यात्री बिठाने में लायी जाने पर यातायात नियमों के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिये। इसी प्रकार दुर्ग भिलाई नगर में रात्रि में भारी वाहनों के प्रवेश प्रतिबंधित करने एएसपी यातायात को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देशित किया है।

इससे पूर्व विगत बैठक की पालन प्रतिवेदन पर विभागवार समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने कार्य पूर्णत:/अद्यतन प्रगति/विभागीय कार्यवाही आदि से अवगत कराया। बैठक में जिले की सड़कों में यातायात सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए विभिन्न सुझावों पर विचार विमर्श कर कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिये गये।

गंजपारा कब्रिस्तान के पास लीक हो गया पाइप लाइन

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। नगर पालिक निगम। नगर पालिक निगम दुर्ग क्षेत्र अंतर्गत गंजपारा कब्रिस्तान के पास स्थित बड़ी पेयजल पाइप लाइन में गंभीर लिकेज पाए जाने के कारण पिछले कुछ समय से सड़क पर लगातार पानी बह रहा है। भारी रिसाव की वजह से फिल्टर प्लांट तक आवश्यक मात्रा में रॉ-वॉटर की सप्लाई प्रभावित हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप जलप्रदाय व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

निगम जलकार्य विभाग द्वारा प्राथमिक रूप से स्थल निरीक्षण करने के उपरांत यह पाया गया कि मुख्य पाइप लाइन के क्षतिग्रस्त हिस्से की तत्काल मरम्मत करना आवश्यक है। इसी क्रम में 10 दिसंबर 2025, दिन बुधवार को प्रात: कालीन नियमित जलप्रदाय के बाद पाइप लाइन को बंद कर रिपेयर कार्य किया जाएगा। इस दौरान संबंधित टंकियों से जुड़े क्षेत्रों में जलप्रदाय आंशिक रूप से बाधित रहेगा।

निगम ने बताया कि मरम्मत कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए टीमों को निर्देशित कर दिया गया है। पाइप लाइन को खोलकर क्षतिग्रस्त भाग की कटिंग, ज्वाइंटिंग तथा कम्प्रेशन फिटिंग का कार्य किया जाएगा। मरम्मत के बाद लाइन को टेस्टिंग के लिए चालू किया जाएगा।

प्रभावित टंकियाँ एवं क्षेत्र:

1. शंकर नगर पानी टंकी
2. शक्ति नगर पानी टंकी
3. पद्मनाभपुर पानी टंकी
4. हनुमान नगर पानी टंकी
5. गिरधारी नगर पानी टंकी

निगम प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे आवश्यक उपयोग हेतु जल का भंडारण पूर्व में कर लें।

निगम ने यशवंत यादव के नियुक्तिपत्र को फर्जी बताया

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। नगर पालिक निगम, दुर्ग के संज्ञान में यह मामला आया है कि यशवंत यादव, सहायक ग्रेड-03 के नाम से एक कथित नियुक्ति पत्र सोशल मीडिया एवं विभिन्न माध्यमों में प्रसारित किया जा रहा है। निगम प्रशासन द्वारा की गई प्रारंभिक जाँच में यह पाया गया है कि यह नियुक्ति पत्र पूर्णत: फर्जी, भ्रामक और अवैध है।

निगम ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा इस प्रकार का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, न ही उक्त व्यक्ति की किसी प्रकार की पदस्थापना नगर पालिक निगम, दुर्ग में की गई है। प्रस्तुत पत्र में शासन के आदेश क्रमांक, तिथि एवं शर्तों का जिस प्रकार उल्लेख किया गया है, वह शासन के अधिकृत प्रारूप से मेल नहीं खाता तथा दस्तावेज की सत्यता संशयास्पद पाई गई है।

निगम प्रशासन ने बताया कि फर्जी पत्र में एक वर्ष में कंप्यूटर प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने, दो वर्ष की परिवीक्षावधि, स्वास्थ्य प्रमाणपत्र एवं थाना क्षेत्र से प्रस्तुत करने, जैसी शर्तों का उल्लेख किया गया है। ये विवरण न तो विधिवत जारी किसी आदेश से संबंधित हैं और न ही निगम के अभिलेखों में उपलब्ध हैं।

नगर निगम, दुर्ग ने स्पष्ट किया है कि इस तरह के फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार करना, प्रसारित करना या इसका उपयोग करना कानूनी अपराध है। निगम प्रबंधन ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए दस्तावेज की सत्यता जाँच हेतु संबंधित विभागों को रिपोर्ट भेज दी है। आवश्यकता पड़ने पर इस मामले में कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाएगी।

निगम ने नागरिकों, अभ्यर्थियों एवं कर्मचारियों से अपील की है कि किसी भी नियुक्ति, पदस्थापना अथवा स्थानांतरण आदेश की सत्यता की पुष्टि के लिए केवल निगम की आधिकारिक वेबसाइट, कार्यालय या संबंधित विभाग से ही जानकारी प्राप्त करें। किसी भी भ्रामक दस्तावेज पर विश्वास न करें और संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल निगम को दें।

जेसीआई दुर्ग-भिलाई का प्रेसिडेंशियल विंटर गाला

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। जेसीआई दुर्ग-भिलाई के वार्षिक कैलेंडर का बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम प्रेसीडेंशियरल विंटर गाला 2025 7 दिसम्बर 2025, रविवार को होटल सेंट्रल पार्क, भिलाई में अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।

अध्यक्ष जेसी आलोक रचना अग्रवाल ने बताया कि पूरे वर्ष भर सभी पूर्व अध्यक्षों वरिष्ठ सदस्य गण तथा नये साथियों का जबरदस्त सहयोग हमें प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मिलता रहा जिसकी वजह से ही यह कार्यकाल अविस्मरणीय बन गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वर्षभर संगठन और समाज हित में समर्पित योगदान देने वाले सदस्यों का सम्मान करना और टीम स्पिरिट को मजबूत करना था।

उन्होंने जेसी सदस्यों को टोकन ऑफ लव भेंट कर उनका सम्मान किया। आयोजन को आकर्षक विंटर थीम से सजाने और मनोरंजक गतिविधियों से भरने में प्रोग्राम डायरेक्टर्स जेसी नकेश सुमन मोदी एवं जेसी वासी अफरीन खान का विशेष योगदान रहा। विंटर थीम से सजे हुए इस आयोजन में मनोरंजक गेम्स, इंटरैक्टिव एक्टिविटीज और म्यूजिक ने वातावरण को जीवंत बनाए रखा। सभी सदस्यों ने थीम आधारित परिधानों में भाग लेकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम का समापन सभी सदस्यों के साथ मिलकर डिनर और ग्रुप फोटो के साथ हुआ जिसने इस ठंडी शाम को और भी खुशनुमा बना दिया।

आंध्रा देवांग समाजम का पारीवारिक मिलन समारोह

देवेन्द्र ने आंध्रा समाज को विधायक निधि से दिए 3 लाख

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। आंध्रा देवांग समाजम का पारिवारिक मिलन समारोह 7 दिसंबर को रामेश्वर महादेव मंदिर परिसर सेक्टर-6 में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में भिलाई नगर विधायक देवेन्द्र यादव उपस्थित हुए। उन्होंने ने मंदिर परिसर के विकास के लिए विधायक निधि से 3 लाख रुपए देने की घोषणा की।

कार्यक्रम में एचटीसी के डायरेक्टर व समाज सेवी इंद्रजीत सिंह छोटू अति विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। एमआईसी सदस्य लक्ष्मीपति राजू विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान विधायक देवेन्द्र यादव ने आंध्रा देवांग समाजम के सदस्यों बातचीत की। उन्होंने रामेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की और विश्वास दिलाया कि वे आगे भी समाज के उत्थान के लिए आगे रहेंगे। आयोजन की सराहना करते हुए उन्होंने मंदिर परिसर में बोर खनन व शौचालय निर्माण के लिए 3 लाख रुपए विधायक निधि से देने की घोषणा की। कार्यक्रम के दौरान लक्ष्मीपति राजू ने तेलुगू समाज के प्रत्येक धड़े को एकजुट होने और साथ मिलकर आगे बढ़ने प्रेरित किया।

अति विशिष्ट अतिथि एचटीसी के डायरेक्टर व सर्व समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह 'छोटू' ने आश्वस्त किया वे समाज की हर संभव मदद के लिए तत्पर रहेंगे। उनकी संस्था सर्व समाज कल्याण समिति द्वारा जरूरत मंदों को हमेशा मदद पहुंचाई जाती है, चाहे वे किसी भी समाज से हों। सर्व समाज कल्याण समिति की ओर से मलकित सिंह 'लल्लू', अनिल चौधरी, जोगा राव, निर्मल सिंह, शाहनवाज कुरैशी, रमन राव, इंद्रजीत सिंह 'चिंटू', डॉ. हरजीन्दर सिंह, वाजिद अंसारी, हरेंद्र यादव, अनिल सिंह, सोम सिंह आदि उपस्थित रहे।

वरिष्टजनों का सम्मान

कार्यक्रम में आंध्र देवांग समाजम के पूर्व अध्यक्षों व पदाधिकारियों के साथ वरिष्ठजनों का सम्मान भी किया गया। समाज के अध्यक्ष भीमा राव के द्वारा पदाधिकारियों व सहयोगियों को देवांग समाज की आराध्य देवी चौडेश्वरी माता का तैलचित्र भेंट स्वरूप दिया गया। आरंभ में बच्चों ने आकर्षक नृत्य प्रस्तुतियां दीं। कलाकारों को पुरस्कृत किया गया। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे समाज के बच्चों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में समाज के संरक्षक एस. चंद्रशेखर, अध्यक्ष जी. भीमा राव, कोषाध्यक्ष पी. रामाराव, उपाध्यक्ष जी. मुकेश, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष वाई. ईश्वरी, महासचिव के. यशोदा, उपाध्यक्ष आई. ईश्वरी, के. मोहन राव, एम. लोकेश, जी. पूर्णिमा, के. शंकर राव, पी. चलपति और ए. गोपाल सहित वरिष्ठ सदस्यों ने कार्यक्रम को सफल बनाया।

स्कंदाश्रम में 39 लोगों ने किया रक्तदान

भिलाई। हुडको स्थित स्कंदाश्रम में रविवार को मॉडल ब्लड बैंक मेकाहारा रायपुर के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 39 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। इस दौरान डोनेट किए गए ब्लड को डॉ. भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल रायपुर के ब्लड बैंक में सुरक्षित रखा जाएगा ताकि जरूरतमंदों को समय पर रक्त मिल सके। हास्पिटल ने सभी रक्तदाताओं को धन्यवाद स्वरूप प्रमाण-पत्र और उपहार प्रदान कर सम्मानित किया गया। स्कंदाश्रम की गुरु मां शिवरंजनी दीदी ने सभी रक्तदाताओं से कहा कि खून अमूल्य है और इसे पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, इसलिए रक्तदान को सर्वोच्च दान माना जाता है। 20 दिसंबर की सुबह स्कंदाश्रम परिसर में बवासीर शिविर का आयोजन होगा।

Since 1972
CROWN-TV®
Choice Of Millions
Washing Machine / Cooler
Available All Size

CONTACT :
Atlas Radio Traders (Crown)
Sect.-3, D-48, Ward No. 22
Devendra Nagar, Raipur (C.G.) 492009
Near Akash Gas Agency Line

खास खबर

विवि की भूमि पर अतिक्रमण का मामला पहुंचा राजभवन

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने बस्तर स्थित शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय की भूमि पर अवैध कब्जा और अन्य निर्माण कार्य किए जाने को गंभीरता से लेते हुए इस पर तत्काल कार्रवाई करने और भूमि को यथावत रखने के निर्देश दिए हैं। श्री डेका ने लोकभवन में मुख्य सचिव विकास शील से इस संबंध में चर्चा की और निर्देश दिया कि विश्वविद्यालय की जमीन पर कब्जा और अनाधिकृत निर्माण हटाया जाए और भूमि को यथावत विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में सुरक्षित रखा जाए। राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि विश्वविद्यालय की भूमि पर किसी भी तरह के अतिक्रमण, बाहरी निर्माण या अन्य गतिविधि शिक्षा के अधिकार, संस्थागत विकास और भविष्य की पीढ़ियों के हितों के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्र का यह विश्वविद्यालय अध्ययन, अनुसंधान और विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए स्थापित किया गया है। इस पर अतिक्रमण या राजनीतिक-प्रशासनिक हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं होगा।

स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति को अक्षुण्ण रखने राज्यपाल की पहल

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने स्वतंत्रता सेनानियों और देश की रक्षा में अपना जीवन समर्पित करने वाले पूर्व सैनिकों की स्मृति को संरक्षित करने के लिए ठोस कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल श्री डेका ने रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह से इस संबंध में चर्चा की। उन्होंने विशेष रूप से स्वतंत्रता सेनानी रामकृष्ण तिवारी का उल्लेख किया जिन्होंने आजादी के आंदोलन में परिवार सहित अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। उन्होंने जेल, त्याग और संघर्ष की कठिन यातनाएं झेलीं। उनसे जुड़े अभिलेख, विरासत को संरक्षित रखने के लिए निर्देश दिया। श्री डेका ने रायपुर में ऐसी पहचान योग्य जगहों की पहचान करने तथा वहां स्मारक, सूचना पट्ट या मेमोरियल गैलरी के रूप में संरक्षित करने के भी निर्देश दिए। राज्यपाल ने कहा कि यह कार्य प्रशासन की पहल और समाज के सहयोग से मिलकर किया जाना चाहिए, तभी उनकी स्मृतियां अविस्मरणीय बन पाएंगी।

दंडामी लक्जरी रिसॉर्ट चित्रकोट में जनजातीय व्यंजन स्पर्धा

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्थापना के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड ने राज्य के सांस्कृतिक और पर्यटन संवर्धन के लिए विशेष गतिविधियों की एक श्रृंखला शुरू की है। इस श्रृंखला के तहत 09 दिसंबर 2025 को दंडामी लक्जरी रिसॉर्ट, चित्रकोट बस्तर में एक अनूठी पारंपरिक छत्तीसगढ़ी एवं जनजातीय व्यंजन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। यह प्रतियोगिता प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जनजातीय पाक शैलियों को उजागर करने का महत्वपूर्ण अवसर है। इसमें भारत के किसी भी हिस्से से 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के प्रतिभागी भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता के माध्यम से स्थानीय व्यंजनों, छत्तीसगढ़ी एवं जनजातीय संस्कृति और छत्तीसगढ़ पर्यटन को नया आयाम मिलेगा। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार के रूप में 7000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 5000 रुपये और तृतीय पुरस्कार के रूप में 3000 रुपये नगद प्रदान किए जाएंगे। सभी विजेताओं को प्रमाणपत्र दिए जाएंगे। सहभागिता हेतु +91-99261-60586 पर संपर्क करें।

बारनवापारा अभ्यारण्य में जंगल सफारी, स्टे और टिकटिंग की ऑनलाइन सुविधा

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य को डिजिटल रूप से और अधिक सुलभ एवं आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आज नया रायपुर में इसकी नई ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट bwsanctuary.com का लोकार्पण किया गया। यह शुभारंभ प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) अरुण पांडेय द्वारा किया गया। इस अवसर पर वनमण्डलाधिकारी बलौदाबाजार धम्मशील गणवीर तथा अधीक्षक बारनवापारा अभ्यारण्य कृषानू चन्द्राकार भी उपस्थित रहे।

ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से अब पर्यटक घर बैठे ही बारनवापारा जंगल सफारी की बुकिंग कर सकेंगे। बारनवापारा के पर्यटन ग्राम एवं देवहिल्स नेचर रिसॉर्ट में ठहरने के लिए भी ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। इस प्लेटफॉर्म पर टिकट उपलब्धता, सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान एवं आगमन की पूरी प्रक्रिया को अत्यंत सरल और पारदर्शी बनाया गया है।

बारनवापारा के पर्यटन ग्राम एवं देवहिल्स नेचर रिसॉर्ट में ठहरने की ऑनलाइन बुकिंग इसके साथ ही बारनवापारा के पर्यटन ग्राम एवं देवहिल्स नेचर रिसॉर्ट में ठहरने की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा भी वेबसाइट में उपलब्ध है, जिससे पर्यटकों को सफारी, आवास और पर्यटन संबंधी सभी सेवाएँ एक ही प्लेटफॉर्म पर सुगमता से प्राप्त होंगी। नई वेबसाइट में मोबाइल फ्रेंडली इंटरफेस होने के कारण इसका उपयोग यात्रियों के लिए बेहद सहज रहेगा। वेबसाइट में फर्जी बुकिंग पर प्रभावी रोक, सटीक रिकॉर्ड-प्रबंधन तथा वन विभाग को बुकिंग डेटा की वास्तविक समय में निगरानी की सुविधा भी उपलब्ध है।

रेलयात्रियों को मिलेगी विश्व स्तरीय खान-पान एवं ब्रांडेड शॉपिंग सुविधा

दपूमरे मुख्यालय बिलासपुर में हुआ विशेष कॉन्फ्रेंस, बनी सहमति

श्रीकंचनपथ समाचार

बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के वाणिज्य विभाग द्वारा आज दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय, बिलासपुर में एक विशेष कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें देश और विदेश के प्रतिष्ठित खाद्य एवं रिटेल ब्रांडों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया । इस सम्मेलन का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर प्रीमियम ब्रांड कैटरिंग आउटलेट तथा कंपनी-स्वामित्व/संचालित सिंगल-ब्रांड प्रीमियम स्टोर्स की स्थापना के अवसरों पर विस्तृत चर्चा करना था, ताकि यात्रियों को आधुनिक हवाई अड्डों की तरह विश्वस्तरीय सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा सकें ।

रेलवे बोर्ड द्वारा कैटरिंग पॉलिसी 2017 में किए गए नवीन संशोधन के तहत प्रीमियम ब्रांड कैटरिंग आउटलेट को कैटरिंग स्टॉल की नई श्रेणी के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय खाद्य ब्रांडों के कंपनी-स्वामित्व/संचालित या फ्रेंचाइज मॉडल के आउटलेट अब रेलवे कैटरिंग ढाँचे का हिस्सा बन सकेंगे। रेलवे स्टेशनों पर ट्रैवल एक्सेसरीज, स्पोर्ट्स, परिधान, फुटवियर और अन्य वस्तुओं के लिए भी सिंगल-ब्रांड प्रीमियम स्टोर्स स्थापित किए जाएंगे।

इतना ही नहीं, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अपने क्षेत्र की विविध स्थानीय व्यंजनों को प्रोत्साहित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। क्षेत्रीय/स्थानीय खानपान एवं मिलेट्स आधारित लोकप्रिय खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देने के लिए स्टेशनों पर कॉम्पैक्ट मॉड्यूलर काउंटर्स स्थापित करने का प्रस्ताव भी इस पहल का हिस्सा है, जिससे स्थानीय उद्यमियों को अवसर मिलेगा और यात्रियों को स्थानीय स्वाद का अनुभव होगा।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने इच्छुक प्रीमियम ब्रांडों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) आमंत्रित किए हैं। ब्रांडों को अपने प्रस्ताव में स्टेशन विवरण, आवश्यक क्षेत्रफल, प्रस्तावित सेवाएँ, तकनीकी अनुभव तथा संचालन योजना जैसी जानकारियाँ प्रस्तुत करनी होंगी । स्टॉल आवंटन की पूरी प्रक्रिया ई-नीलामी के माध्यम से पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक ढंग से की जाएगी, जो किसी भी प्रकार के नामांकन आधारित आवंटन को समाप्त करती है। सभी स्टॉलों की अवधि पाँच वर्ष निर्धारित की गई है।

आज आयोजित कॉन्फ्रेंस में कोकाकोला, नेसकैफे, अमूल, हल्दीराम, मोतीमहल, बीकाजी, डोमिनोज, बर्गर किंग, बर्गर सिंह, सबवे, ब्रिटेनिया, पिज्जा हट, अरुण आइसक्रीम, लवज्जा कॉफी तथा अन्य राष्ट्रीय ब्रांडों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके साथ ही शहरों की पहचान बन चुके स्थानीय ब्रांड जैसे दुर्ग के श्री जलाराम और तृप्ति, रायपुर के चाय गोविंदम, तथा बिलासपुर के मौसाजी और एबीजा, गढ़ कलेवा और सीजी हर्बल ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसरपर इंटरएक्टिव सत्र का भी आयोजन किया गया जिसमें कई सुझाव भी मिले।

छत्तीसगढ़ को मिले तीन नए आईएएस अधिकारी

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (यूपीएससी सीएसई 2024) के आधार पर आईएएस अधिकारियों के कैडर आवंटन की सूची जारी कर दी है। इस बार के ऑल इंडिया टॉपर शक्ति दुबे को उनका होम स्टेट उत्तर प्रदेश कैडर मिला है।

इधर छत्तीसगढ़ को तीन नए आईएएस अधिकारी मिले हैं। साथ ही यूपीएससी 2024 में 65वीं रैंक हासिल करने वाली छत्तीसगढ़ कैडर की आईपीएस पूर्वा अग्रवाल को इस बार झारखंड कैडर मिला है।

कैडर आवंटन जारी होने के बाद नए अधिकारी अपने-अपने राज्यों में प्रशिक्षण और नियुक्ति प्रक्रिया के लिए रिपोर्ट करेंगे।

छत्तीसगढ़ को मिले 3 नए आईएएस अधिकारी

उम्मीदवार	होम स्टेट	आवंटित कैडर
गोकुल आर.के.	तमिलनाडु	छत्तीसगढ़
वाध्यता यशवनाथ	तेलंगाना	छत्तीसगढ़
इशांत जायसवाल	उत्तर प्रदेश	छत्तीसगढ़

यूपीएससी टॉपर्स के कैडर आवंटन

शक्ति दुबे	उत्तर प्रदेश
हर्षिता गोयल	गुजरात
डोंगरे अर्चित पराग	कर्नाटक
शाह मार्गी चिराग	गुजरात
आकाश गर्ग	AGMUT
कोमल पुनिया	उत्तर प्रदेश
आयुषी बंसल	मध्य प्रदेश
राजकृष्ण झा	बिहार
आदित्य विक्रम अग्रवाल	उत्तर प्रदेश
मयंक त्रिपाठी	उत्तर प्रदेश

निपनिया-भाटापारा ट्रिपल लाइन पर 15 किलोमीटर स्वचालित सिगनलिंग

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (दपूमरे), रायपुर मंडल ने निपनिया - भाटापारा ट्रिपल लाइन सेक्शन पर 15 किलोमीटर की नई 'स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली' को सफलतापूर्वक शुरू कर दिया गया है। 6 और 7 दिसंबर, 2025 के बीच पूरा किया गया यह प्रमुख बुनियादी ढांचा उन्नयन, सेक्शन में ट्रेनों की गति, सुरक्षा और परिचालन क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

थ्रूपुट और सुरक्षा में वृद्धि इस ट्रिपल-लाइन सेक्शन पर स्वचालित सिग्नलिंग में परिवर्तन ट्रेनों को कम अंतराल पर चलने की अनुमति देता है, जिससे 'हेडवे' (दो ट्रेनों के बीच का समय) काफी कम हो जाता है और कुल लाइन क्षमता बढ़ जाती है।

'स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली' का कार्य तीनों लाइंस में से एक-एक लाइन का 'डिसकनेक्शन ब्लॉक' लेकर सम्पूर्ण किया गया है ताकि यात्रियों को कम से कम व्यवधान हो।

स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली सुविधाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

15 किमी के इस सेक्शन में 28 नए ऑटोमैटिक सिग्नल और 12 नए सेमी-ऑटोमैटिक सिग्नल लगाए गए है। ट्रेनों की सटीक स्थिति की जानकारी के लिए पूरे सेक्शन में 'जीजी ट्रोनिक्स' के मल्टी सेक्शन डिजिटल एक्सल काउंटर के 146 डिटेक्शन पाइंट्स लगाए गए है। पूरे सिस्टम को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए एक्सल काउंटर दोहरी पहचान और मीडिया विविधता के साथ लगाए गए हैं। यह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उच्च विश्वसनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

दो लेवल क्रॉसिंग गेट को सिग्नलिंग सिस्टम के साथ पूरी तरह से इंटरलॉक किया गया है, और महत्वपूर्ण उपकरणों को रखने के लिए तीन नए 'ऑटो हट्स' बनाए गए हैं। निर्बाध संचालन और वास्तविक समय की त्रुटि निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सभी नए प्रतिष्ठानों पर 'स्टैटकॉन' के इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई और 'एफ्फट्रोनिक्स' के डेटा लॉगर्स की स्थापना की गई है। मिड-लाइन (मध्य लाइन) के लिए एक समर्पित 'डायरेक्शन सेटिंग पैनल' स्थापित किया गया है, जो पीक परिचालन मांगों को संभालने के लिए द्विदिशा यातायात प्रबंधन को सक्षम बनाता है।

7 दिसंबर की शाम को निपनिया यार्ड की सफल कमीशनिंग ने इस महत्वपूर्ण परियोजना के पूरा होने को चिह्नित किया। यह अपग्रेड रेल बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और यात्रियों व माल ढुलाई के लिए सुरक्षित तथा कुशल यात्रा सुनिश्चित करने के लिए दपूमरे रायपुर मंडल की निरंतर प्रतिबद्धता का हिस्सा है।

1.83 लाख मतदाताओं ने छोड़ दिया शहर?

बिलासपुर। जिले में चल रहे एसआईआर के दौरान चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। जिले के कुल 16.75 लाख मतदाताओं में से 4.33 लाख से अधिक मतदाताओं के फॉर्म बीएलओ वापस नहीं ले सके। इनमें से बड़ी संख्या या तो शहर छोड़ चुकी है, मृत हो चुकी है या अपने पते पर नहीं है। जिला निर्वाचन कार्यालय के मुताबिक 1,83,645 मतदाता अपने पंजीकृत पते से शिफ्ट हो चुके हैं। 1,30,117 मतदाता बीएलओ को अपने पते पर नहीं मिले। 71,663 मतदाताओं की मृत्यु की पुष्टि हुई है।

नए श्रम कानूनों पर यूनियनों ने जताई चिन्ता

श्रीकंचनपथ समाचार

कोरबा। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2020, 29 श्रम कानूनों को समेट कर चार श्रम संहिता क्रमशः वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध सहिता सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य व कार्य शर्त संहिता 2020 में बदल दिया है। इसकी अधिसूचना जारी हो गई है। भारतीय मजदूर संघ को छोड़कर देश के सभी केंद्रीय श्रम संगठन ने विरोध किया है।

एटक कोल फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीपेश मिश्रा ने कहा कि नए कानून से कमजोर श्रमिक मालिकों की दया पर छोड़ दिए गए है। पहले जहां 20 कर्मचारी काम करते थे तो फैक्ट्री एक्ट था। अब उसकी संख्या बढ़ाकर 100 कर दी गई है। इससे छोटे कारखाने एक्ट कानून के दायरे से बाहर हो जाएंगे। मौजूदा कानून के तहत यदि किसी फैक्ट्री में 100 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं तो उसे बंद करने के लिए सरकार की मंजूरी लेनी होती है जबकि नये कोड में यह संख्या 300 कर दी गई है।

इसी तरह वेतन संहिता 2019 में न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, वेतन भुगतान अधिनियम 1936, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 तथा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को मिला दिया गया है। समान वेतन का सपना दिखाकर मजदूरों के हित में बने कानून को चालाकी से खत्म कर दिया गया है।

अभी मजदूरों का न्यूनतम वेतन त्रिपक्षीय कमेटी जिसमें ट्रेड यूनियस, कॉर्पोरेट तथा सरकार के प्रतिनिधियों के माध्यम से निर्धारित होती है परंतु नए वेज कोड में सिर्फ सरकार के नौकरशाह द्वारा मजदूरों का पक्ष जाने बिना ही एक तरफा फ्लोरवेज (न्यूनतम वेतन) तय कर दी जाएगी।

लोकतांत्रिक ढांचे में कैग की भूमिका सर्वोच्च - राज्यपाल

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। महालेखाकार कार्यालय आवासीय परिसर के सामुदायिक भवन में आयोजित ऑडिट पखवाड़ा समापन समारोह में मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि लेखा परीक्षा केवल सरकारी व्यय और राजस्व की जांच तक सीमित नहीं है, यह प्रशासनिक पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन, और जनसेवा में उत्तरदायित्व का एक सशक्त माध्यम है। हमारे लोकतांत्रिक ढांचे में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की सर्वोच्च भूमिका है।

राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग का इतिहास गौरवशाली रहा है। इसकी नींव ब्रिटिश शासन के दौरान 1858 में प्रारंभ हुई लेखा परीक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई है। स्वतंत्रता के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने इस संस्था की महत्ता को समझते हुए इसे संवैधानिक प्राधिकरण का दर्जा प्रदान किया।

श्री डेका ने कहा कि तेजी से बढ़ते डिजिटल प्रशासन के दौर में कैग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। यह संस्था केवल कमियों को उजागर नहीं करती, बल्कि प्रशासनिक सुधार, नवाचार एवं पारदर्शिता को प्रोत्साहित करती है।

यह न केवल सरकारी कार्यों में वित्तीय अनुशासन लाने का कार्य करता है, बल्कि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को रोकने का महत्वपूर्ण दायित्व भी निभाता है। इस विभाग के अधिकारियों की निष्पक्षता और कर्मठता ने इसे एक सशक्त संस्थान के रूप में स्थापित किया है।

बालोद में होगा पहला राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी

स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने किया शुभंकर का अनावरण

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। प्रथम राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी 2026 का आयोजन बालोद जिले के डौण्डीलोहारा विकासखण्ड के ग्राम दुधली में 09 से 13 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव द्वारा स्थल पर विधिवत पूजा-अर्चना एवं भूमिपूजन के साथ किया गया। मंत्री श्री यादव ने इस अवसर पर राजकीय पशु 'वन भैंसा' पर आधारित शुभंकर तथा 'विकसित युवा, विकसित भारत' थीम पर आधारित लोगो का अनावरण भी किया।

स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी 2026 में देश के विभिन्न राज्यों से 15 हजार से अधिक रोवर और रेंजर शामिल होंगे। यह आयोजन न केवल युवाओं की सहभागिता का अद्भुत संगम होगा, बल्कि इसमें राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री सहित अनेक गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति कार्यक्रम की गरिमा को और अधिक बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन युवाओं में अनुशासन, सहयोग और आपसी भाईचारे की भावना को मजबूत बनाता है। उन्होंने सभी नागरिकों और विभागीय अधिकारियों से इस राष्ट्रीय कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु सहयोग की अपील की।

भारत स्काउट गाइड, छत्तीसगढ़ के राज्य मुख्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा ने शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव के नेतृत्व में प्रथम राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी के आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह अवसर छत्तीसगढ़ राज्य के लिए गौरव की बात है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य यशवंत जैन ने इस वृहद राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी का अवसर देने के लिए शिक्षा मंत्री का धन्यवाद व्यक्त किया।

जिला मुख्य आयुक्त राकेश यादव ने कहा कि बालोद में इतने महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय आयोजन का होना अत्यंत गर्व की बात है और यह आयोजन निश्चित रूप से ऐतिहासिक और यादगार बनेगा।

कार्यक्रम में कलेक्टर बालोद, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत के सीईओ, जंबूरी डायरेक्टर अमर क्षेत्री तथा स्काउट-गाइड अधिकारी और सदस्य सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

नेहरू नगर में डामरीकरण एवं सड़क कार्यों का निरीक्षण

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने आज जोन-1 नेहरू नगर क्षेत्राधिकार के अंतर्गत चल रहे निर्माणाधीन डामरीकरण एवं स्वीकृत सड़क कार्यों का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ वार्ड 12 के पार्षद एवं सभापति गिरवर बंटी साहू भी उपस्थित थे।

आयुक्त ने निर्माणाधीन और स्वीकृत सड़कों का जायजा लिया और अधिकारियों को वार्ड में नागरिकों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं जैसे सड़क, नाली और बिजली की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया।

आयुक्त ने विशेष रूप से शिक्षक नगर में सड़क नंबर 9, 10, 11 और आर्य नगर की ओर जाने वाली सड़क पर किए जा रहे नवीन डामरीकरण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने अभियंताओं को कड़े निर्देश दिए कि सड़क निर्माण का कार्य उत्कृष्ट गुणवत्ता के साथ किया जाए, जिससे यह लंबे समय तक टिकाऊ बना रहे।

निरीक्षण के दौरान निगम के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें जोन आयुक्त अजय राजपूत, कार्यपालन अभियंता संजय अग्रवाल, उप अभियंता, पुरुषोत्तम सिन्हा, बसंत साहू, रीमा झामूलकर, सहायक राजस्व अधिकारी सुनील जोशी तथा स्वच्छता निरीक्षक कमलेश द्विवेदी शामिल थे। आयुक्त ने कहा कि निगम का लक्ष्य है कि भिलाई के हर नागरिक को बेहतर बुनियादी ढाँचा और सुविधाएँ उपलब्ध हों।

गंजेपन से मुक्ति
मात्र 1 घंटे में
COMPLETE FAMILY SALON
हेयर रिप्लेसमेंट, 100% संतुष्टि की गारंटी
पहले बाद में
JITU'Z
CUT N SHINE
93009-11331
रंगोली बेंगल्स के सामने, जयसवाल इलेक्ट्रानिक के बाजू में इंदिरा मार्केट, स्टेशन रोड, दुर्ग (छ.ग.)

GST NO. 22AHMPB9621P1Z2
PH.: 0788-4060131
अनुप ट्रेडर्स
आर्टिफिशियल ज्वेलरी के विक्रेता
लिंक रोड, केम्प-2, पावर हाउस, भिलाई
मो. 09826389666, 8839749539

प्रतिभा रांटा के हाथ लगी नागजिला

कार्तिक आर्यन की बनीं हीरोइन

सिनेमाई दुनिया में नए सितारे तेजी से चमक रहे हैं और उनमें से एक हैं प्रतिभा रांटा। अपनी पहली ही फिल्म लापता लेडीज से उन्होंने दर्शकों का ध्यान खींचा और अब उन्हें कार्तिक आर्यन की आने वाली क्रिएचर कॉमेडी नागजिला में लीड हीरोइन बनने का मौका मिल गया है। लापता लेडीज में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए बेस्ट लीड एक्ट्रेस क्रिटिक्स का फिल्मफेयर पुरस्कार जीतने वाली प्रतिभा के लिए बेशक ये बड़ा मौका है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, लापता लेडीज में धूम मचाने वाली प्रतिभा अब कार्तिक आर्यन की फिल्म नागजिला: नाग लोक का पहला कांड में लीड रोल में नजर आने वाली हैं। निर्देशक मृगदीप सिंह लाम्बा की इस क्रिएचर कॉमेडी फिल्म की शूटिंग इसी हफ्ते शुरू हुई है। इसके लिए निर्माता-निर्देशक ने पहले अभिनेत्री सान्या मल्होत्रा का नाम फाइनल किया था, लेकिन आखिरकार प्रतिभा ने बाजी मारते हुए फिल्म अपने नाम कर ली।

प्रतिभा के पास मैडॉक फिल्म्स के साथ एक फिल्म है, जिसकी शूटिंग 2026 की शुरुआत में शुरू होगी। अगर तारीखों पर पेंच नहीं फंसा तो वो कार्तिक के साथ नागजिला में मुख्य भूमिका निभाएंगी। मृगदीप और निर्माता उन्हें फिल्म में लेने को उत्सुक हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अभी पर्दे पर ज्यादा उभरकर सामने नहीं आई हैं। बता दें कि कार्तिक नागजिला में इच्छाधारी नाग प्रियंवदेश्वर प्यारे चंद की भूमिका निभाएंगे। इस फिल्म के निर्माता करण जौहर हैं।

लापता लेडीज में जया के किरदार के लिए सुर्खियां बटोरने वाली प्रतिभा का जन्म शिमला में हुआ था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मॉडलिंग की और फिर मुंबई आ गईं। इसके बाद उनके अभिनय करियर की शुरुआत टीवी शो कुर्बान हुआ से हुई। हालांकि, किरण राव की लापता लेडीज से उनकी किस्मत चमकी। इसके बाद प्रतिभा को संजय लीला भंसाली की हीरामंडी भी मिली, जिसने उनके करियर में चार-चांद लगा दिए। इंस्टाग्राम पर प्रतिभा के 13 लाख फॉलोअर्स हैं।

आदि साई कुमार फिल्म शम्भाला-ए मिस्टिकल वर्ल्ड का ट्रेलर रिलीज़, 25 दिसंबर को होगी रिलीज़

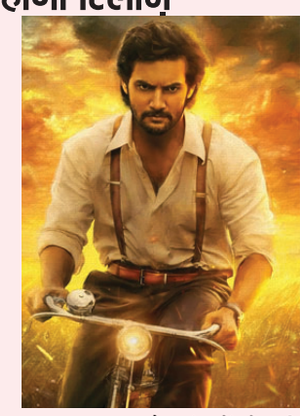

आदि साई कुमार एक दिलचस्प और रोमांचक एंटरटेनर शम्भाला- ए मिस्टिकल वर्ल्ड लेकर आ रहे हैं। उगंधर मुनि द्वारा डायरेक्ट की गई यह फिल्म 25 दिसंबर 2025 को क्रिसमस स्पेशल के तौर पर रिलीज़ हो रही है।

मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ किया। पैन इंडिया स्टार प्रभास ने ट्रेलर रिलीज़ किया और मेकर्स को शुभकामनाएं दीं। ट्रेलर एक वॉइस ओवर से शुरू होता है और फिर दर्शकों को हज़ारों साल पहले भगवान शिव और एक खतरनाक राक्षस के बीच हुई एक भयानक लड़ाई की जड़ों में ले जाया जाता है। इस कॉस्मिक लड़ाई के दौरान, शिव का पसीना धरती पर गिरने से एक भयानक धमाका होता है, जिससे एक रहस्यमयी आसमानी घटना पैदा होती है। अग्नि पुराण के अनुसार, ऐसी कॉस्मिक लड़ाइयाँ जानवरों के ज़रिए भी दिखने वाली अंधेरी ताकतों को जगा सकती हैं।

आदि साई कुमार एक ऐसे नौजवान के रोल में दिख रहे हैं जो एक दूर-दराज के गांव में हो रही रहस्यमयी घटनाओं को सुलझाने निकला है। सिनेमैटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूज़िक ने सीन को और भी दिलचस्प बना दिया है। साई कुमार ने वॉइस ओवर दिया है और इससे ज़बरदस्त असर पड़ा है। अर्चना अय्यर, स्वासिका, रवि वर्मा, मधुनंदन, और शिवा कार्तिक और दूसरों को ट्रेलर में दिखाया गया है। श्रीचरण पकाला ने म्यूज़िक ट्यून किया है जबकि सिनेमैटोग्राफी प्रवीण के बंगारी ने की है। महिधर रेड्डी और राजशेखर अन्नाभिमोजू शाइनिंग पिक्चर्स बैनर पर फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं।

यश अभिनीत टॉक्सिक की टीम ने अफवाहों को किया खारिज, 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म

टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स के निर्माताओं ने फिल्म की देरी से रिलीज की अफवाहों पर विराम लगाते हुए रिलीज डेट की पुष्टि कर दी है। जानिए यश अभिनीत बहुप्रतीक्षित फिल्म टॉक्सिक को आप सिनेमाघरों में कब देख सकेंगे।

कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर जानकारी आई थी कि यश फिल्म के कुछ हिस्सों से खुश नहीं हैं और दोबारा शूटिंग करवाना चाहते हैं। इसलिए फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ सकती है, लेकिन ये सिर्फ अफवाहें थीं।

निर्माताओं का जवाब केवीएन प्रोडक्शंस ने एक्स हैंडल पर देते हुए यश का एक शानदार पोस्टर शेयर किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, अभी 140 दिन बाकी हैं। टॉक्सिकद मूवी 19-03-2026 को रिलीज होगी।

ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श ने एक्स हैंडल पर जानकारी देते हुए लिखा, अफवाहों पर विराम लगाएं... यश की अगली फिल्म टॉक्सिक में देरी या देरी नहीं हुई है। टॉक्सिक 19 मार्च 2026 को रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है, जो उगादी, गुड़ी पड़वा और ईद के त्यौहारी सप्ताहांत के लिए बिल्कुल सही समय पर है।

पोस्ट-प्रोडक्शन तब शुरू हुआ जब यश मुंबई में फिल्म रामायण की शूटिंग कर रहे थे। टीम अब शूटिंग के अंतिम हिस्से को पूरा कर रही है और जनवरी 2026 में इसका प्रचार शुरू होगा। यह फिल्म अंग्रेजी और कन्नड़ में एक साथ शूट की गई है। टॉक्सिक को हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम सहित कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में भी डब किया जाएगा।

केजीएफ के बाद यश की ये पहली बड़ी फिल्म है। फैंस को लंबे इंतजार के बाद थिएटर में उनकी वापसी दिखेगी। टॉक्सिक का निर्देशन गीतू मोहनदास ने किया हैय् फिल्म का निर्माण यश और वेंकट के नारायण ने किया है। इस फिल्म को केवीएन प्रोडक्शंस और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस बैनर तले निर्मित किया जा रहा है। फिल्म की शूटिंग का आखिरी शैड्यूल बेंगलुरु में चल रहा है। फिल्म का पोस्ट-प्रोडक्शन का काम अप्रैल 2025 से शुरू हुआ, जब यश रामायण की शूटिंग कर रहे थे।

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे का सोशल मीडिया पर अक्सर बोल्ड अंदाज देखने को मिलता रहता है। वह अपने फोटोज से अपने तमाम चाहने वाले फैंस का ध्यान खींचती हैं। अनन्या पांडे ने हाल ही में अपने लेटेस्ट फोटोशूट की झलक दिखाई है और अपनी बोल्ड अदाओं से सोशल मीडिया का पारा बढ़ा दिया है। एक्ट्रेस के फैंस तो उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं, वही, कई यूजर्स को उनका अंदाज पसंद नहीं आया और उन्होंने एक्ट्रेस को ट्रोल किया है। आइए जानते हैं कि अनन्या पांडे को लेकर लोगों ने क्या लिखा है।

फिल्म के प्रमोशन के दौरान अनन्या पांडे ने बिकिनी में दिए पोज

अनन्या पांडे ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इन फोटोज में अनन्या पांडे का दिलकश अंदाज चर्चा का विषय बना हुआ है।

अनन्या पांडे ने फोटोशूट के दौरान मोनोकिनी पहनकर एक से बढ़कर पोज दिया। अनन्या पांडे का कातिलाना अंदाज उनके फैंस को घायल कर रहा है।

अनन्या पांडे ने फोटोशूट के दौरान मोनोकिनी पहनकर एक से बढ़कर पोज दिया। अनन्या पांडे का कातिलाना अंदाज उनके फैंस को घायल कर रहा है।

अनन्या पांडे की तस्वीरों को देखकर फैंस उनकी तारीफ करते हुए कमेंट कर रहे हैं। एक फैन ने लिखा है, वाह क्या अदाएं हैं। एक फैन ने लिखा है, खूबसूरत

अनन्या पांडे का ये अंदाज कई लोगों को पसंद नहीं आया। एक यूजर ने लिखा है, ऐसे कपड़े पहनने से सुंदर नहीं बन जाओगी. एक यूजर ने लिखा है, ये सब क्या है।

कंधे में दर्द होने पर आजमाएं ये घरेलू नुस्खे जल्द मिलेगा आराम

कंधे में दर्द होना एक आम समस्या है, जो किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है। यह दर्द अक्सर गलत मुद्रा में बैठने, भारी सामान उठाने या अचानक किसी चीज को खींचने के कारण होता है। इससे रोजमर्रा की गतिविधियों में काफी दिक्कत होती है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान घरेलू नुस्खे बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने कंधे के दर्द को कम कर सकते हैं और जल्दी राहत पा सकते हैं।

गर्म सिकाई करें

गर्म सिकाई कंधे के दर्द को कम करने का एक सरल और प्रभावी तरीका हो सकता है। इसके लिए एक गर्म पानी की बोतल लें और उसे दर्द वाले हिस्से पर लगाएं। इसे लगभग 15-20 मिनट तक लगाकर रखें। यह रक्त प्रवाह बढ़ाने में मदद करता है और मांसपेशियों की जकड़न को कम करता है। ध्यान रखें कि पानी बहुत गर्म न हो, वरना त्वचा को जलन हो सकती है। नियमित रूप से इसका उपयोग करें।

हल्दी का सेवन करें

हल्दी में खास तत्व होते हैं, जो सूजन कम करने में मदद करते हैं। यह गुण कंधे के दर्द को कम करने में सहायक हो सकता है। एक गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर पीने से शरीर में सूजन कम होती है और दर्द में राहत मिलती है। इसके अलावा आप हल्दी को खाने में भी शामिल कर सकते हैं, जिससे आपके शरीर को प्राकृतिक रूप से दर्द निवारण हो सके।

तिल का तेल लगाएं

तिल का तेल ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होता है, जो मांसपेशियों की सूजन कम करने में मदद करता है। इस तेल को हल्का

गर्म करके प्रभावित क्षेत्र पर मालिश करें। इससे रक्त प्रवाह बढ़ता है और दर्द में राहत मिलती है। नियमित रूप से इस उपाय का उपयोग करने से आपके कंधे की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और दर्द की समस्या कम होती है। यह एक सुरक्षित और प्रभावी घरेलू नुस्खा है, जिसे आप आजमा सकते हैं।

अदरक की चाय पिएं

अदरक में ऐसे तत्व होते हैं, जो दर्द निवारक की तरह काम करते हैं। एक कप पानी में कुछ टुकड़े ताजे अदरक के डालकर उबालें, फिर इसे छानकर पीएं। इससे आपके शरीर की अंदरूनी सूजन कम होती है और दर्द में राहत मिलती है। अदरक की चाय पीने से न केवल कंधे का दर्द कम होता है, बल्कि यह आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है। नियमित रूप से इसका सेवन करें।

योग और स्ट्रेचिंग करें

योग और स्ट्रेचिंग कसरत करने से भी कंधे का दर्द कम हो सकता है। विशेषकर उन योगासनों का अभ्यास करें, जो कंधों की मांसपेशियों को खींचते-खिंचते हैं जैसे भुजंगासन, वीरभद्रासन आदि। इसके अलावा रोजाना 10-15 मिनट स्ट्रेचिंग करने से भी फायदा होता है। इन घरेलू नुस्खों को अपनाकर आप अपने कंधे के दर्द से जल्दी राहत पा सकते हैं और अपनी दिनचर्या को बिना किसी रुकावट के जारी रख सकते हैं।

सुबह जल्दी जागने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके

सुबह जल्दी उठना एक अच्छी आदत है, जो आपके दिन को सकारात्मक और उत्पादक बना सकती है। यह आदत न केवल आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, बल्कि आपके समय का सही उपयोग करने में भी मदद करती है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप सुबह जल्दी उठने की आदत डाल सकते हैं और अपने दिन की शुरुआत बेहतर तरीके से कर सकते हैं।

सोने का समय तय करें

रात को सोने का एक निश्चित समय निर्धारित करें और उसे नियमित रूप से पालन करें। इससे आपका शरीर एक निर्धारित समय पर सोने के लिए तैयार हो जाएगा। यह आदत आपको पर्याप्त नींद लेने में मदद करेगी और सुबह जल्दी उठने की संभावना बढ़ाएगी। ध्यान रखें कि आपको 7-8 घंटे की नींद लेनी चाहिए ताकि आप ताजगी महसूस करें और दिन की शुरुआत ऊर्जा से भरपूर हो।

सुबह उठते ही पानी पिएं

सुबह उठते ही एक गिलास पानी पीना बहुत फायदेमंद हो सकता है। यह आपके शरीर को तरोताजा करता है और आपके खाने को पचाने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। इसके अलावा यह आपके पेट को जागृत करता है और शरीर से गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है। अगर आप चाहें तो इसमें नींबू का रस या शहद मिला सकते हैं, जिससे यह और भी पौष्टिक बन जाएगा और आपको ताजगी का एहसास होगा।

हल्की कसरत करें

सुबह-सुबह हल्की कसरत करना आपके शरीर और मन दोनों के लिए अच्छा होता है। इससे न केवल आपकी शारीरिक ताकत बढ़ती है बल्कि मानसिक स्थिति भी बेहतर होती है। आप योग, स्ट्रेचिंग या हल्की दौड़ आदि कर सकते हैं। इससे आपका खून का दौरा बेहतर होता है और ऊर्जा स्तर बढ़ता है। नियमित कसरत से आपका दिन सकारात्मक और ऊर्जावान रहेगा, जिससे आप हर काम में अधिक उत्साह और ताजगी महसूस करेंगे।

नाश्ता करना न भूलें

सुबह का नाश्ता सबसे अहम है, जिसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पौष्टिक नाश्ता आपके ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है और पूरे दिन के लिए तैयार करता है। इसके अलावा यह आपकी एकाग्रता क्षमता को भी सुधारता है और आपको स्वस्थ बनाए रखता है। नाश्ते में फल, दही या ओट्स शामिल करें ताकि आपकी डाइट संतुलित रहे। इन सरल तरीकों को अपनाकर आप आसानी से सुबह जल्दी उठने की आदत डाल सकते हैं और अपने दिन की शुरुआत बेहतर बना सकते हैं।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रयासों से धरातल तक उतर रही युवाओं के सर्वांगीण विकास की योजनाएं

नालंदा परिसर युवाओं के उज्जवल भविष्य की बुनियाद, भोरमदेव विद्यापीठ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का बना सशक्त केंद्र

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा के बीते दो वर्षों के प्रयासों ने कवर्धा में युवाओं के सर्वांगीण विकास की एक नई इबारत तैयार हो रही है। युवाओं व विद्यार्थियों के खेल तथा शिक्षा सुविधाओं को सुदृढ़ करने के ध्येय के साथ धरातल पर उतरती योजनाओं ने युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है।

जिनमें आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नालंदा परिसर का निर्माण, विद्यार्थियों के लिए हाई टेक स्मार्ट क्लास, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भोरमदेव विद्यापीठ का संचालन, खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए कई जगहों पर मिनी स्टेडियम का निर्माण के साथ एस आई भर्ती परीक्षा परिणाम जारी करवाने जैसे कार्य शामिल हैं।

यह सभी विकास कार्य बताते है कि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के नेतृत्व में कवर्धा में पिछले दो वर्षों में शिक्षा, खेल, युवा सशक्तिकरण और आधारभूत विकास के क्षेत्र में कई दूरगामी पहल की गयी है। उनका यह प्रयास न केवल वर्तमान बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत और उम्मीदों से भरा आधार तैयार कर रहा है। कवर्धा में छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी विस्तार देते हुए 4 करोड़ 41 लाख रुपये की लागत से नालंदा परिसर निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है।

भूमिपूजन के पश्चात अब निर्माण कार्य तेजी से शुरू कर दिया है। नालंदा परिसर भविष्य में विद्यार्थियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक गतिविधियों और संसाधनों का केंद्र बनेगा। यहां छात्रों को उन्नत लाइब्रेरी, डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त संसाधन मिलेंगे। जो छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा और उच्च शिक्षा की तैयारी के लिए एक मजबूत बुनियाद तैयार करने में सहायक सिद्ध होंगे। छह वर्षों से लंबित 975 पदों की एसआई भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाना और उसका परिणाम जारी कराना उप मुख्यमंत्री के प्रयासों से संभव हुआ है। इस भर्ती में कबीरधाम जिले के 40 युवाओं का चयन होना पूरे जिले के लिए गर्व की बात है।

यह उपलब्धि युवाओं के मन में नई ऊर्जा और विश्वास भरती है कि युवाओं के रोजगार के अवसर मजबूत हो रहे हैं।

50 स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम - शिक्षा में डिजिटल क्रांति

शिक्षा के आधुनिकीकरण को ध्यान में रखते हुए कवर्धा विधानसभा के 50 सरकारी स्कूलों में बड़े निजी स्कूलों की तर्ज पर स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए गए हैं। इससे विद्यार्थियों को डिजिटल माध्यम से सीखने-समझने का अवसर मिल रहा है। स्मार्ट क्लासरूम बच्चों को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ते हुए शिक्षा को अधिक रोचक, प्रभावी और बहुआयामी बना रहे हैं।

भोरमदेव विद्यापीठ : प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों का समग्र केंद्र

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की स्पष्ट सोच है कि आ संसाधनों के कमी के चलते जिले के होनहारों की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में कहीं कमी न हो। वे इस ध्येय को धरातल पर मूर्त रूप देने का कार्य भोरमदेव विद्यापीठ संचालन की पहल से कर रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए समग्र संसाधन केंद्र के रूप में तैयार हुआ है। भोरमदेव विद्यापीठ के माध्यम से प्रति वर्ष 200 प्रतिभावान युवाओं को सीजी पीएससी और सीजी व्यापम परीक्षाओं की निशुल्क तैयारी की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस पहल से ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के छात्र-छात्राओं को उच्च गुणवत्ता की कोचिंग मिल रही है और सिविल सेवा जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं को हासिल करने का रास्ता उनके लिए आसान हुआ है।अनुभवी शिक्षक, सटीक रणनीति, सिलेबस के अनुसार स्टडी मटेरियल और मार्गदर्शन प्रतिभागियों की तैयारी पुख्ता हो रही है।

झलमला में नया कॉलेज, कवर्धा पीजी कॉलेज का विस्तार

सुदूर वनांचल झलमला में नए कॉलेज खोले जाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जिससे आदिवासी क्षेत्र के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वहीं, कवर्धा के पीजी कॉलेज के विस्तार कार्य में भी तेजी लाई गई है, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएँ एवं अधिक विषयों में अध्ययन का अवसर उपलब्ध होगा।

मंत्री नेताम ने मध्यप्रदेश के राज्यपाल से की मुलाकात

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ के कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने अपने भोपाल, प्रवास के दौरान मध्यप्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल से भोपाल स्थित राजभवन में सौजन्य मुलाकात की।

राज्यपाल पटेल से मुलाकात के दौरान मंत्री नेताम ने छत्तीसगढ़ राज्य में विकास और जनकल्याण की योजनाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्य मंत्री विष्णु देव साय की नेतृत्व वाली सरकार, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, युवाओं, किसानों सहित सभी वर्गों के विकास के कार्य कर रही हैं।

मंत्री नेताम ने बताया कि देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के मंशानुरूप राज्य में जनजातीय समाज के विकास के लिए पीएम जनमन और धरती आबा अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है और 3100 रूपए प्रति क्विंटल मूल्य दिया जा रहा है, जो देश में सर्वाधिक है।

उन्होंने राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल से छत्तीसगढ़ आने निवेदन भी किया।

छत्तीसगढ़ में निवेश की तैयारीः बेंगलुरु में उद्योगपतियों संग सांसद बृजमोहन की बैठक

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। बेंगलुरु प्रवास के दौरान रविवार को रायपुर लोकसभा सांसद एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कर्नाटक के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापना को बढ़ावा देना रहा।

इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रमुख उद्योगपति अशोक हिसारिया, जय प्रकाश गुप्ता, चंदू भाई, राम सारिया, प्रभात किशनपुरीया, सुभाष अग्रवाल तथा मुरारीलाल सरावगी विशेष रूप से उपस्थित रहे और छत्तीसगढ़ में निवेश संभावनाओं पर गहन चर्चा की। सांसद अग्रवाल ने उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि, छत्तीसगढ़ देश के सबसे तेज़ी से उभरते औद्योगिक राज्यों में से एक है। यहाँ उद्योग लगाने के लिए आवश्यक सभी सुविधाएँ, नीतिगत समर्थन, अधोसंरचना और निवेशकों के लिए सुरक्षित एवं अनुकूल वातावरण राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह सुनिश्चित किया जा रहा है।

उन्होंने यह भी बताया कि, उद्योग स्थापना हेतु सिंगल विंडो सिस्टम के तहत सरल और तेज़ स्वीकृतियाँ, सस्ती एवं पर्याप्त बिजली आपूर्ति, उत्तम लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी, उद्योगों के लिए भूमि उपलब्धता, कौशलयुक्त मानव संसाधन तथा प्रधानमंत्री मोदी की औद्योगिक विकास समर्थक नीतियाँ छत्तीसगढ़ को निवेश के लिए एक आदर्श राज्य बनाती हैं। उद्योगपतियों ने छत्तीसगढ़ की संभावनाओं को अत्यंत उत्साहजनक बताते हुए मैन्युफैक्चरिंग, स्टील-प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप इनक्यूबेशन और अन्य सेक्टरों में निवेश करने की इच्छा जताई।

सांसद अग्रवाल ने सभी उद्योगपतियों को छत्तीसगढ़ आमंत्रित करते हुए आश्वस्त किया कि जो भी उद्योगपति छत्तीसगढ़ में उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें सरकार की ओर से हर आवश्यक सुविधा, सहयोग और सुरक्षा प्रदान की जाएगी। हमारा लक्ष्य है, उद्योग बढ़ें, रोजगार बढ़े और प्रदेश आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत बने। बैठक सफल, सकारात्मक और अत्यंत प्रेरणादायी रही तथा आगामी समय में इसके ठोस परिणाम सामने आने की पूर्ण उम्मीद है।

बारनवापारा अभ्यारण्य में जंगल सफारी, स्टे और टिकटिंग की ऑनलाइन सुविधा

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य को डिजिटल रूप से और अधिक सुलभ एवं आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आज नया रायपुर में इसकी नई ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट bwsanctuary.com का लोकार्पण किया गया। यह शुभारंभ प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) अरुण पांडेय द्वारा किया गया। इस अवसर पर वनमण्डलाधिकारी बलौदाबाजार धम्मशील गणवीर तथा अधीक्षक बारनवापारा अभ्यारण्य कृषानू चन्द्राकार भी उपस्थित रहे।

ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से अब पर्यटक घर बैठे ही बारनवापारा जंगल सफारी की बुकिंग कर सकेंगे। बारनवापारा के पर्यटन ग्राम एवं देवहिल्स नेचर रिसॉर्ट में ठहरने के लिए भी ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। इस प्लेटफ़ॉर्म पर टिकट उपलब्धता, सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान एवं आगमन की पूरी प्रक्रिया को अत्यंत सरल और पारदर्शी बनाया गया है। इसके साथ ही बारनवापारा के पर्यटन ग्राम एवं देवहिल्स नेचर रिसॉर्ट में ठहरने की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा भी वेबसाइट में उपलब्ध है, जिससे पर्यटकों को सफारी, आवास और पर्यटन संबंधी सभी सेवाएँ एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर सुगमता से प्राप्त होंगी। नई वेबसाइट आधुनिक तकनीक से तैयार की गई है तथा मोबाइल फ्रेंडली इंटरफ़ेस होने के कारण इसका उपयोग यात्रियों के लिए बेहद सहज रहेगा। वेबसाइट में फर्जी बुकिंग पर प्रभावी रोक, सटीक रिकॉर्ड-प्रबंधन तथा वन विभाग को बुकिंग डेटा की वास्तविक समय में निगरानी की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त व्हाट्सऐप आधारित हैसल-फ्री टिकटिंग की सुविधा भी जोड़ी गई है, जिससे पर्यटक और भी आसानी से बुकिंग कर सकेंगे।

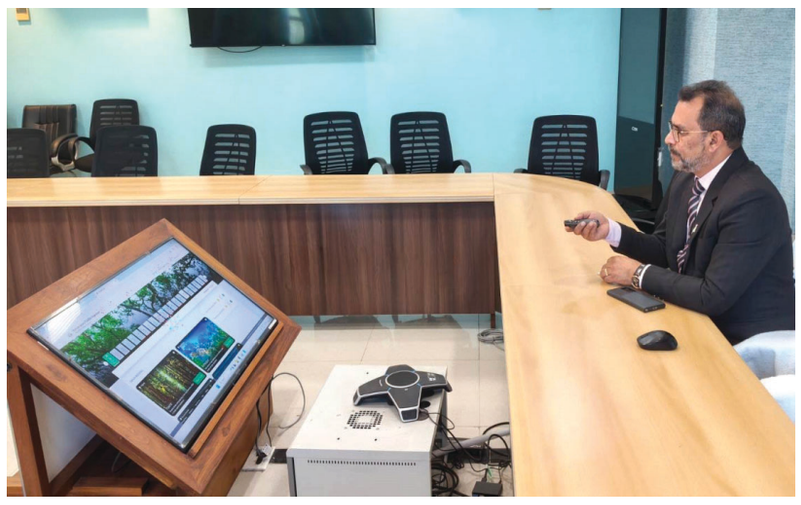

पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पूर्व योजना के अंतर्गत 60 दिन पहले तक एडवांस बुकिंग करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इससे पर्यटकों को अपनी यात्रा समय रहते तय करने की सुविधा मिलेगी और अभ्यारण्य प्रबंधन को भी सुरक्षित एवं नियंत्रित पर्यटन संचालन में सहयोग मिलेगा।

वाटरशेड महोत्सव में श्रमदान के साथ जल संरक्षण का संदेश

बलरामपुर। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत विकासखंड रामचंद्रपुर के ग्राम देवीगंज में वाटरशेड महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें जिला पंचायत सदस्य एवं कृषि स्थाई समिति के द्वारा जल संरक्षण विषय पर विस्तृत जानकारी दी गई परियोजना अधिकारी रॉबिंसन सुधीर कुजूर के द्वारा वाटरशेड महोत्सव कार्यक्रम के बारे में जल और मृदा की उपयोगिता पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में स्कूली छात्र-छात्राओं के द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई साथ ही अमृत सरोवर और सिंचाई नाली के साफ सफाई में श्रमदान किया गया। इस दौरान करमा नृत्य के साथ साथ स्कूली छात्र-छात्राओं के लिए जल संरक्षण पर आधारित रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत ग्रामीण एवं स्कूली छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

सबका साथ-सबका विकास के मूलमंत्र के साथ कार्य कर रही है राज्य सरकारः उद्योग मंत्री

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। प्रदेश के वाणिज्य उद्योग, श्रम, आबकारी व सार्वजनिक उपक्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सबका साथ-सबका विकास - सबका विश्वास के मूलमंत्र के साथ छत्तीसगढ़ सरकार लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में विगत दो वर्ष के कार्यकाल में राज्य सरकार ने पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य करते हुए एक जनहितैषी व जनकल्याणकारी सरकार की छबि बनाई है, उन्होने कहा कि जहाँ तक कोरबा के विकास का प्रश्न है तो विगत दो वर्ष के दौरान नगर निगम कोरबा क्षेत्र के विकास के लिए 800 करोड़ रूपये से अधिक के विकास कार्यो को स्वीकृत दी जा चुकी है तथा बिना किसी भेदभाव के सभी 67 वार्डो में जनता की मांग व आवश्यकता के अनुरूप तेजी से विकास कार्य कराए जा रहे हैं।

उक्त बातें उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने आज कोरबा नगर निगम के वार्ड क्र. 20 पथर्रीपारा में आयोजित भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान कहीं। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा वार्ड क्र. 20 पथर्रीपारा बजरंग बली मंदिर से गीतादेवी के घर तक एवं नीलगिरी बस्ती में 15 लाख रूपये की लागत से सी.सी. रोड का निर्माण तथा वार्ड क्र. 20 कोसाबाड़ी जोनांतर्गत महर्षि वाल्मीकि आश्रम में 10 लाख रूपये की लागत से टायलेट एवं बाथरूम का निर्माण कराया जाना हैं, पथर्रीपारा स्थित महिला दुर्गा पण्डाल परिसर में आयोजित भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने मुख्य अतिथि के रूप में अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान करते हुए उक्त दोनों विकास कार्यो का भूमिपूजन किया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर संजूदेवी राजपूत द्वारा की गई, वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में सभापति नूतन सिंह ठाकुर, गोपाल मोदी, वरिष्ठ पार्षद नरेन्द्र देवांगन सहित निगम की मेयर इन काउंसिल के सदस्यगण व पार्षदगण उपस्थित थे। भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री देवांगन आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दर्जनों जनकल्याणकारी योजनाएं देश में चलाई है, जिनका सीधा लाभ देश के करोड़ों लोगों को मिल रहा है, वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन की दिशा तय करते हुए विगत दो वर्षो के दौरान पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य किया है तथा आमजनता के हित में दर्जनों योजनाएं संचालित की है।

उन्होने आगे कहा कि प्रदेश में 15 वर्ष तक डॉ.रमन सिंह मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं, उन्होने अपने कार्यकाल में अनेकों जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई थी, जिन्हे बीच में बंद कर दिया गया था, अब मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के द्वारा पुनः इन जनहितैषी योजनाओं का संचालन कराया जा रहा है, जिससे प्रदेश के लाखों नागरिक लाभान्वित हो रहे हहै । उद्योग मंत्री देवांगन ने कहा कि कोरबा जिले की सभी सड़कों के जीर्णोद्धार, नवनिर्माण के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है, कार्यो की आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर शीघ्र ही इस दिशा में कार्य होगा।

इस मौके पर महापौर संजूदेवी राजपूत ने अपने उद्बोधन में कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान उद्योग मंत्री देवांगन द्वारा क्षेत्र की जनता से विकास से संबंधित जो भी वायदें किए गए थे, वे सभी वायदें आज पूरे हो रहे हैं, नगर निगम कोरबा क्षेत्र में अरबों रूपये के विकास कार्य स्वीकृत कराए गए हैं।

सरदार वल्लभ भाई पटेल आदर्श राष्ट्र नायक - डॉ. द्विवेदी

राजनांदगांव। लौह पुरूष महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वतंत्रता पश्चात 562 रियासतों का एकीकरण करने वाले अद्वितीय राष्ट्र सेवक सरदार वल्लभ भाई पटेल के समसामयिक पुण्य स्मरण परिप्रेक्ष्य में नगर के वरिष्ठ विचार चिंतक डॉ. कृष्ण कुमार द्विवेदी ने विशिष्ट विमर्श में बताया कि अद्भुत नेतृत्व क्षमता, कठोर अनुशासन, दृढ़संकल्पी और अद्भुत प्रशासनिक कौशल के धनी व्यक्तित्व तथा राष्ट्र के प्रथम उपप्रधानमंत्री, गृहमंत्री सरदार पटेल जी एक श्रेष्ठ, सरल, ईमानदार राजनेता हुए हैं। जिनका समग्र जीवनक्रम आदर्श राष्ट्र भक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है।

राष्ट्र निर्माण में सरदार पटेल का अतीव महत्तम योगदान प्रत्येक भारतीय को सहज-सरल रूप में राष्ट्र के प्रति सर्वदा कर्तव्यनिष्ठ रहने को अभिप्रेरित करता है। इस संदर्भ में आगे डॉ. द्विवेदी ने उल्लेखनीय रूप से बताया कि सरदार पटेल के बहुआयामी व्यक्तित्व एवं सर्वोत्कृष्ट कृतित्व के लिए उन्हें एक से बढक़र एक विशेषणों से संबोधन दिए जाते रहे है।

सरकार की धान खरीदी की पारदर्शी व्यवस्था से ग्राम बेल्हाडीह के किसान समारू को मिली बड़ी राहत

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का अभियान 15 नवंबर से प्रारंभ किया गया है। यह अभियान प्रदेश के किसानों की आर्थिक सुरक्षा को नए आयाम प्रदान कर रहा है। इसी क्रम में विकासखण्ड सक्ती के ग्राम बेल्हाडीह के किसान श्री समारू बंजारे की कहानी सरकार की किसान हितैषी नीतियों और सुचारू पारदर्शी धान खरीदी व्यवस्था की उत्कृष्ट मिसाल के रूप में सामने आई है।

किसान समारू बंजारे ने धान उपार्जन केंद्र बेल्हाडीह में 31.20 क्विंटल धान विक्रय कर समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त किया। धान विक्रय के उपरांत उन्होंने शासन एवं प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के प्रति संतोष व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि वर्तमान खरीदी व्यवस्था सहज, सरल और किसानों के लिए अत्यंत सुविधाजनक है, जिससे उन्हें बिना किसी परेशानी के अपना धान बेचने में आसानी हो रही है।

श्री बंजारे ने बताया कि पहले

टोकन के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ता था और पूरा दिन निकल जाता था, जिससे खेती-किसानी का काम भी प्रभावित होता था। अब मोबाइल फोन से ही ऑनलाइन टोकन प्राप्त हो जाता है और समय पर सूचना भी मिल जाती है। इसके चलते खरीदी केंद्र पहुंचते ही तुरंत तौलाई हो जाती है, जिससे न केवल समय की बचत हो रही है बल्कि अनावश्यक भीड़ और अव्यवस्था की समस्या भी समाप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था ने किसानों की मेहनत, समय और संसाधनों तीनों की ही बचत सुनिश्चित की है।

किसान समारू बंजारे ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा लागू की गई ऑनलाइन टोकन प्रणाली को किसानों के हित में अत्यंत लाभकारी बताया। उन्होंने कहा कि खरीदी केंद्रों में अब त्वरित तौलाई, पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। इन सुविधाओं ने किसानों में शासन-प्रशासन के प्रति भरोसा बढ़ाया है और उन्हें आत्मविश्वास के साथ अपना धान बेचने का अवसर मिला है। किसानों का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था ने खरीदी प्रक्रिया को पूरी तरह व्यवस्थित और प्रभावी बना दिया है।

सक्ती जिले में धान खरीदी अभियान को अत्यंत सुव्यवस्थित ढंग से संचालित किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने पर्याप्त संसाधन, पारदर्शी प्रक्रिया और बेहतर प्रबंधन के माध्यम से खरीदी केंद्रों को सुचारू बनाया है। इससे न तो भीड़ की समस्या उत्पन्न हो रही है और न ही किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यह व्यवस्था राज्य सरकार की किसान हितैषी सोच और उनके लिए बनाई गई योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को प्रदर्शित करती है।

खास खबर

शांति व्यवस्था भंग करने वाले पांच लोगों पर कार्यवाही

राजनांदगांव। जिले की थाना सोमनी पुलिस ने थानाक्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग करने के मामले में पांच लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की है। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा (भापुसे) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहूल देव शर्मा के मार्गदर्शन, नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र नायक के पर्यवेक्षण में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना प्रभारी सोमनी निरीक्षक अरूण कुमार नामदेव के नेतृत्व में ग्राम देवादा में पुलिस में रिपोर्ट करने की बात से आक्रोशित होकर शांति एवं कानून व्यवस्था भंग करने की नियत से प्रार्थी से वाद विवाद कर रहे पांचा आरोपी रवि गोसाई पिता राजमल गोसाई उम्र 24 वर्ष, राज वैष्णव पिता गुरूववन दास उम्र 22 वर्ष, रवि कुकरेजा पिता स्व. लीलाधर कुकरेजा उम्र 40 वर्ष, प्रकाश मणी पिता गुरू दयाल उम्र 41 वर्ष तथा टिमन उर्फ ऋषि नेताम पिता लोकेश प्रसाद उम्र 23 वर्ष सभी निवासी ग्राम मुड़ीपार थाना सोमनी जिला राजनांदगांव को धारा 170 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार कर अनावेदको को प्रतिबंधित करने पृथक से धारा 126,135(3) बीएनएसएस का इस्तगाशा तैयार कर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट राजनांदगांव के न्यायालय पेश कर आदेशानुसार जेल दाखिल किया गया है।

हाथियों की निगरानी से लौटते समय बड़ा हादसा, पसान रेंजर और चालक गंभीर रूप से घायल

कोरबा। जिले के पसान थाना क्षेत्र में रविवार तड़के सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया। हाथियों की मूवमेंट की जानकारी मिलने पर रातभर ड्यूटी कर वापस लौट रहे वन विभाग के पसान रेंजर मनीष सिंह और उनके चालक की स्कॉर्पियो वाहन पेड़ से टकराने के कारण भीषण दुर्घटना का शिकार हो गई। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। शनिवार देर रात पिपरिया क्षेत्र में हाथियों के पहुंचने की सूचना मिली थी। रेंजर मनीष सिंह और चालक तत्काल मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने तथा छेड़छाड़ न करने की सलाह दी। हाथी मित्र दल की मदद से हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने के बाद दोनों अधिकारी रात में ही वापस लौट रहे थे। वापसी के दौरान पसान रोड पर उनकी स्कॉर्पियो अचानक बेकाबू होकर सड़क किनारे पेड़ से जोरदार टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। राहगीरों ने तत्काल मदद करते हुए दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद रेंजर की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बिलासपुर रेफर कर दिया गया है।

सक्ती में धान से भरा ट्रैक्टर जला, चालक ने कूदकर बचाई जान

सक्ती। सक्ती जिले के मौहाडीह में रविवार को धान से लदा एक ट्रैक्टर अचानक आग की चपेट में आ गया। देखते ही देखते ट्रैक्टर और उस पर रखा पूरा धान जलकर खाक हो गया। यह घटना नगरदा थाना क्षेत्र में हुई। आग लगने के दौरान ट्रैक्टर चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए तुरंत वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई। इस कारण एक बड़ा हादसा टल गया और चालक सुरक्षित रहा। स्थानीय ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया। लेकिन तब तक ट्रैक्टर और धान पूरी तरह जल चुके थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है।

रेप का आरोपी गिरफ्तार, शादी का झांसा देकर किया था दुष्कर्म

श्रीकंचनपथ न्यूज

जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में रेप के आरोपी सहायक पोस्ट मास्टर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आरोपी ने युवती को शादी का झांसा दिया और विश्वास में लेकर दुष्कर्म किया। इसके बाद शादी करने से इनकार करने लगा। इस मामले में पुलिस महिला की शिकायत पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 64(2)(एम) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामला थाना तुमला का है।

इस मामले में 6 दिसंबर 2025 को 35 वर्षीय युवती ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि सौरभ कुमार जो कि मूलत: बिहार का रहने वाला है व वर्तमान में जशपुर के एक पोस्ट ऑफिस में सहायक पोस्ट मास्टर का कार्य करता है। पीड़िता का सौरभ कुमार से 2024 में परिचय हुआ था। पीडिता दूसरे जिले के पंचायत में तकनीकी सहायक के रूप में कार्य कर रही थी। 14 जनवरी 2025 को पीडिता छुट्टी पर अपने गृह ग्राम आई हुई थी, उसी दौरान सौरभ कुमार उसे शादी का झांसा दिया और उससे अनाचार किया। तब से लेकर जून 2025 तक पीड़िता जब भी छुट्टी पर आती तब सौरभ कुमार उसका शारीरिक शोषण किया जाता था।

जब युवती सौरभ कुमार से शादी करने कहा उसने युवती को तकनीक सहायक की नौकरी छोड़ने पर ही शादी करने की बात कही। युवती ने सौरभ कुमार के कहने पर तकनीकी सहायक की नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने पर सौरभ कुमार ने युवती को कुछ दिनों तक अपने साथ रखा और उसके बाद अब शादी करने से इनकार कर रहा है। शादी की बात पर सौरभ कुमार के द्वारा युवती से गाली गलौच किया जाने लगा। इस मामले में शिकायत मिलने के बाद तत्काल पुलिस के द्वारा थाना तुमला में प्रार्थिया की रिपोर्ट पर आरोपी सौरभ कुमार के विरुद्ध बी एन एस की धारा 64 (2)(एम) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया गया।

मामले में पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी सहायक पोस्ट मास्टर संतोष कुमार को हिरासत में लिया गया। पूछताछ पर आरोपी सौरभ कुमार के द्वारा अपराध स्वीकार करने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि जशपुर पुलिस महिलाओं से संबंधित अपराधों को लेकर अत्यंत संवेदनशील है, तुमला क्षेत्रांतर्गत एक युवती से, शादी का झांसा दे दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

ऐसे अपराधों में संलिप्त किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी तुमला निरीक्षक कोमल सिंह नेताम, आरक्षक बसंत खुटिया, सोनू सिंह, हीरालाल यादव व महिला आरक्षक बीरजिनिया टोप्पो की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

एसडीएम की रेड में 35 ट्रैक्टर रेत-गिट्टी जब्त पेड़ काटकर ले जा रहा वाहन पकड़ा

गौरेला मरवाही। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (एसडीएम) पेंड्रारोड, विक्रांत अंचल के नेतृत्व में, ग्राम केंवची में दो अलग-अलग महत्वपूर्ण कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया है, जिसमें अवैध रेत खनन और शासकीय भूमि पर वृक्षों की अवैध कटाई का खुलासा हुआ है। इन कार्रवाइयों ने स्थानीय प्रशासन की तत्परता और अवैध गतिविधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति को पुन: रेखांकित किया है।

एसडीएम पेंड्रारोड विक्रांत अंचल ने ग्राम केंवची का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान, ग्राम निवासी बिमलेश मार्को द्वारा अवैध रूप से बड़ी मात्रा में रेत का भंडारण किया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान, लगभग 35 ट्रैक्टर-ट्राली रेत और 3 ट्रॉली गिट्टी को अवैध रूप से भंडारित पाया गया। प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इस अवैध भंडार को जब्त कर लिया और ग्राम पंचायत सरपंच को सुपुर्दगी में दे दिया। इस कार्रवाई के समय हल्का पटवारी विनोद राठौर, ग्राम कोटवार, सरपंच और ग्रामवासी भी मौके पर उपस्थित थे। यह घटना क्षेत्र में अवैध रेत खनन और भंडारण की समस्या को उजागर करती है।

इसी ग्राम केंवची में एक और गंभीर मामला सामने आया, जहां ग्राम के ही निवासी पंचरत्न जैन ने शासकीय भूमि पर लगे पुराने सेमरा वृक्ष को अवैध रूप से काटा। काटी गई लकड़ी को वाहन क्रमांक सीजी 10 आर 0870 में अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। जैसे ही प्रशासन को इस बात की भनक लगी, मौके पर पहुँचने पर वाहन चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए वन विभाग को सूचित किया और मौके पर बुला लिया। वन विभाग के अधिकारियों ने पंचनामा तैयार कर अवैध रूप से काटी गई लकड़ी और वाहन को वन विभाग के वन परिक्षेत्राधिकारी के सुपुर्दगी में सौंप दिया, ताकि आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके।

कोंडागांव मर्डर का खुलासा : एक थप्पड का बदला लेने कुल्हाड़ी से काट दिया सिर

श्रीकंचनपथ न्यूज

कोंडागांव। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में तीन दिन पहले मिली लाश का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। आपसी रंजिश व एक थप्पड़ का बदला लेने हत्या की खौफनाक साजिश रची गई। आरोपी ने युवक का कुल्हाड़ी से गला काट दिया। कटे हुए सिर को एक थैली में भरकर तालाब किनारे गड्ढा खोदकर दफना दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब आरोपी के मोबाइल से हत्या का एक वीडियो मिला। इसके बाद पुलिस आरोपी तक पहुंची। इस मामले में एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है वहीं दूसरा फरार है।

5 दिसंबर को विश्रामपुरी जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति की सर कटी लाश मिली थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पाया कि शव का सिर धड़ से पूरी तरह गायब था। एसपी के निर्देश पर विशेष टीम गठित की और फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड की मदद से घटनास्थल की बारीकी से जांच की गई। पुलिस ने शव के कपड़ों के आधार पर उसकी पहचान बाड़ागांव निवासी लछीन्दर पांडे के रूप में की।

शिनाख्ती के बाद आरोपी तक पहुंची पुलिस

शव की शिनाख्ती के बाद पुलिस के लिए आरोपी तक पहुंचना आसान हो गया। विवेचना के दौरान पुलिस को मुखबिर से पता चला कि मृतक लछीन्दर का कुछ दिन पहले विश्रामपुरी साप्ताहिक बाजार में श्यामलाल नेताम और रामू नेताम से विवाद हुआ था। उसने विवाद के दौरान श्यामलाल नेताम को थप्पड़ जड़ दिया था। पुलिस को जांच के दौरान यह भी पता चला कि लछीन्दर आदतन बदमाश था। आए दिन लोगों से झगड़ा करता था।

संदेही के मोबाइल में मिला वीडियो

पुलिस ने संदेह के आधार पर श्यामलाल नेताम को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उसने पुलिस को गुमराह करना शुरू कर दिया। इसके बाद जब पुलिस ने संदेही का मोबाइल चेक किया तो उसमें एक वीडियो मिला जिसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। वीडियो में हत्या का पूरा प्रकरण रिकार्ड था। इससे पूरा मामला खुल गया। पुलिस की सख्ती से पूछताछ के बाद श्यामलाल ने पूरी सच्चाई बता दी। उसने बताया कि लछीन्दर को बहला-फुसलाकर जंगल की ओर ले जाया गया। सड़क से लगभग 1 किलोमीटर भीतर ले जाकर कुल्हाड़ी और टंगिए से लगातार 17 वार किए गए। फिर लछीन्दर का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। कटे हुए सिर को एक थैली में भरकर तालाब किनारे गड्ढा खोदकर दफनाया गया। फिलहाल आरोपी श्यामलाल नेताम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दूसरा आरोपी रामू नेताम फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीम लगातार दबिश दे रही है।

शराब के अवैध बिक्रीकर्ता आरोपी गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। दुर्ग जिले की पुरानी भिलाई थाना पुलिस ने सोमवार को पुरैना डेम नर्सरी क्षेत्र से एक आरोपी को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 33 पौवा अवैध 'शोले मसाला' शराब बरामद की गई है। पकड़े गए आरोपी को न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल भेज दिया गया है।

जानकारी के अनुसार, 8 दिसंबर की सुबह पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि पुरैना डेम नर्सरी के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब बेच रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर संदिग्ध को पकड़ा।

पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम दशरथ पारधी (50 वर्ष) बताया जो गनियारी का रहने वाला है।

बोरी में भरकर रखा था शराब

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक प्लास्टिक की बोरी जब्त की, जिसमें चंदौसी सिहौरी सरबती ब्रांड का लेबल लगा था। बोरी में कुल 33 पौवा शोले मसाला शराब भरी हुई थी। हर एक पौवा में 180 एमएल शराब होने से कुल मात्रा 5940 एमएल पाई गई। बरामद शराब की अनुमानित कीमत 3300 रुपए बताई गई है।

आरोपी को भेजा गया जेल

पुलिस के अनुसार, आरोपी अवैध शराब बिक्री कर अवैध रूप से धन अर्जित कर रहा था। उस पर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत कार्रवाई की गई है। मामले में अपराध दर्ज कर आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया।

इसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन विश्वास अभियान के तहत जिलेभर में अवैध शराब एवं अन्य नशे के कारोबार के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है।

गांजा तस्करी मामले में फरार मुख्य आरोपी गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। जिले की उतई थाना पुलिस ने रविवार को एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में लंबे समय से फरार चल रहे मुख्य आरोपी सत्येंद्र कुमार उर्फ संजू बिहारी को उसके निवास स्थान से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अपने घर पर छुपकर रह रहा था।

बता दें कि 16-17 अक्टूबर को पुलिस ने अवैध रूप से गांजा तस्करी के मामले में मुख्य आरोपी सत्येंद्र कुमार के साथी सिद्धार्थ मेश्राम, यनशु वर्मा, विजयकांत वर्मा और संजीव वर्मा को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया था वहीं मुख्य सप्लायर संजू बिहारी फरार हो गया था। जिसकी पुलिस लगातार खोजबीन कर रही थी। इस दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी सत्येंद्र कुमार उर्फ संजू अपने परसदा स्थित घर में छुपकर रहा रहा है।

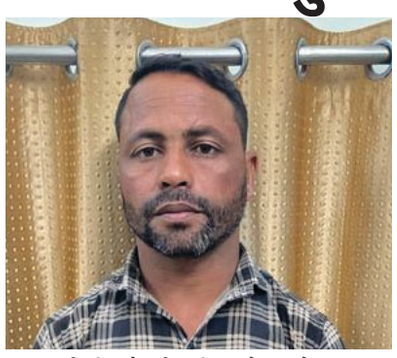

जानकारी मिलते ही पुलिस ने उसके घर पर छापामार कार्यवाही करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे मेडिकल जांच के बाद न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। उतई थाना पुलिस ने बताया कि मामले की विवेचना अभी जारी है और तस्करी से जुड़े अन्य बिंदुओं पर गहराई से जांच की जा रही है।

बताया जाता है कि आरोपी सत्येंद्र कुमार उर्फ संजू मूल रूप से ग्राम मूर्तिपुर टिकैत का रहने वाला था और वर्तमान में ग्राम परसदा में रह रहा था।

संजू ओडिशा से बड़े पैमाने पर गांजा लाकर सप्लाई करता था तथा उन पैसों से लग्जरी लाइफ भी जी रहा था और पुलिस की निगरानी से बचने के लिए बार-बार मोबाइल बदलता था और कई बार ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच मूव करता रहता था। तस्करी का बड़ा नेटवर्क संचालित करता था अधिकारियों के अनुसार, संजू बिहारी का नेटवर्क काफी विस्तृत था। वह गांजा तस्करी में शामिल कई छोटे-बड़े सप्लायरों और खरीदारों से जुड़ा था। पुलिस अब उसके बैंक खातों, सम्पत्ति और अन्य नेटवर्क की भी जांच कर रही है। संभावना है कि आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

अवैध शराब बेचने के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज

बलौदाबाजार। जिले की थाना भाटापारा ग्रामीण पुलिस ने अवैध रुप से शराब बिक्री करने वाले 02 आरोपी शराब कोचियों को गिरफ्तार किया है तथा उनके कब्जे से 414 पाव देशी मसाला शराब जब्त किया है।

मिली जानकारी के अनुसार 07 दिसम्बर को समाधान सेल में प्राप्त सूचना के आधार पर थाना भाटापारा ग्रामीण एवं साइबर सेल की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा ग्राम अर्जुनी रोड में घेराबंदी कर स्कूटी के माध्यम से अवैध रूप से बिक्री करने के लिए शराब ले जाते।

02 आरोपियों पंकज डहरिया उम्र 22 साल निवासी भगत सिंह वार्ड भाटापारा थाना तथा आशीष धृतलहरे उम्र 20 साल निवासी भगत सिंह वार्ड भाटापारा थाना भाटापारा शहर को गिरफ्तार किया गया है।

आरोपी शराब कोचियों से 41,400 कीमत मूल्य का 414 पाव देशी मसाला शराब एवं अवैध रूप से शराब परिवहन में प्रयुक्त एक स्कूटी क्रमांक सीजी 04 एनटी 2697 जप्त किया गया है।

आरोपियों पंकज डहरिया उम्र 22 व धृतलहरे उम्र 20 साल के विरुद्ध थाना भाटापारा ग्रामीण में धारा 34(2) आबकारी के तहत प्रकरण पंजीबध्द कर आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है।

एक दिन में गर्भवती का 2 बार ऑपरेशन,बिगड़ी हालत, मौत

श्रीकंचनपथ न्यूज

सरगुजा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में गर्भवती का एक ही दिन में 2 बार ऑपरेशन कर दिया गया। ऑपरेशन कर डिलीवरी कराई गई। टांके से ब्लड आने पर महिला का यूट्रस (गर्भाशय) निकाल दिया गया। महिला की हालत बिगड़ने पर उसे रायपुर रेफर किया गया। रायपुर के मेकाहारा हॉस्पिटल से महिला को एम्स ले जाने कहा गया। एम्स ने बेड खाली नहीं है कहकर भर्ती करने से इनकार कर दिया। वापस लाने के दौरान महिला की मौत हो गई।

मिली जानकारी के मुताबिक बलरामपुर जिले के त्रिकुंडा थाना क्षेत्र के कृष्णनगर निवासी सुनीता सिंह (35) पति मनीष सिंह 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसे मितानिन संगीता सिंह 4 दिसंबर को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बगड़ा लेकर गई थी। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे बलरामपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया था। जांच के बाद बच्चे को खतरा बताकर उसे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल अंबिकापुर रेफर कर दिया गया। 4 दिसंबर की शाम महिला को लेकर परिजन अंबिकापुर पहुंचे।

सिजेरियन डिलवरी के दूसरे दिन बिगड़े हालत

सुनीता सिंह को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के गायनिक वार्ड में भर्ती किया गया। रात 1.30 बजे उसका सिजेरियन ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन से सुनीता ने 3.40 किलोग्राम के स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। दोनों को डॉक्टरों की देखरेख में रखा गया था। 5 दिसंबर की शाम सुनीता सिंह को लगाए गए टांके से ब्लड आने लगा।

इसकी जानकारी परिजनों ने डॉक्टर को दी। आनन-फानन में सुनीता सिंह को दोबारा ऑपरेशन के लिए ले गए। डॉक्टरों ने परिजनों को बताया कि यूट्रस का रास्ता बंद हो गया है। यूट्रस निकालना पड़ेगा। परिजनों ने इसकी सहमति दे दी। सुनीता सिंह का ऑपरेशन कर यूट्रस निकाल दिया गया।

लेकिन दोबारा हुए ऑपरेशन के बाद सुनीता का यूरिन बंद हो गया। उसकी हालत बिगड़ने लगी। 6 दिसंबर को डॉक्टरों ने हालत बिगड़ती देख उसे रायपुर रेफर कर दिया।

रायपुर में नहीं किया एडमिट, वापस आने के दौरान मौत

मितानिन और परिजनों ने बताया कि वे सुनीता को लेकर रायपुर मेकाहारा हॉस्पिटल पहुंचे। वहां से उसे एम्स ले जाने की सलाह दे दी गई। जब वे एम्स पहुंचे तो बताया गया कि वहां बेड खाली नहीं है। जहां से उसे लेकर आए हो, वहीं वापस चले जाओ। बिना इलाज कराए परिजन सुनीता सिंह को लेकर वापस अंबिकापुर लौट रहे थे। रास्ते में उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले में परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। वहीं, हॉस्पिटल प्रबंधन ने लापरवाही से इनकार किया है।

नाम परिवर्तन

मैं शपथकर्ता पूर्ण चन्द्र दोरा पिता श्री जुगेश्वर दोरा उम्र 36 वर्ष, निवासी Near Block -Rajagalpur, Village Uchhabahal, Rinbachan, Balangir Odisha 767022 का है जो कि निम्नलिखित कथन शपथपूर्वक प्रस्तुत करता हूँ । यह कि छत्तीसगढ शासन वित योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनाय संख्या 01, प्रपत्र 5, भिलाई इस्पात सयंत्र सेक्टर-8 से (जन्म-मृत्यू रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 12/17 तथा छत्तीसगढ जन्म-मृत्यू रजिस्ट्रीकरण नियम 2001 के नियम 8/13 के अंतर्गत जारी किया गया) बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण संख्या B-2017: 22-90311-000621 पुत्री का नाम AYESHA DORA की जन्मतिथि 09.02.2017, जन्म प्रमाण पत्र दिनांक 16.04.2017 को जारी किया गया था। यह कि, उक्त जन्म प्रमाण पत्र मे माता का नाम SANGITA DORA अंकित है जबकि माता के आधारकार्ड संख्या 3382 2774 9874 एवं अन्य दस्तावेजों मे सही नाम SHANGITA DORA है। यह कि, SANGITA DORA व SHANGITA DORA ये दोनो नाम मेरे ही पत्नी के है जो कि एक ही महिला का नाम है। व यह कि भविष्य मे मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र तथा समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं अन्य दस्तावेजों पत्रों में माता का सही नाम SHANGITA DORA दर्ज किया जावें।

शपथकर्ता
पूर्ण चन्द्र दोरा
Near Block -Rajagalpur, Village Uchhabahal, Rinbachan, Balangir Odisha

गाइडलाइन दरों में बदलावः इंक्रीमेंटल प्रणाली समाप्त

अब जिला मूल्यांकन समितियां 31 दिसंबर तक भेजेंगी नए प्रस्ताव

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। राज्य में 20 नवंबर 2025 से लागू नई गाइडलाइन दरों के संबंध में प्राप्त सुझावों, ज्ञापनों और आपत्तियों पर विचार करने हेतु मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक 07 दिसंबर 2025 को आयोजित की गई। बैठक में पंजीयन एवं मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर कई व्यापक निर्णय लिए गए, जो 8 दिसंबर से तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। बैठक में नगरीय क्षेत्रों में भूमि मूल्यांकन के लिए लागू इंक्रीमेंटल आधार पर गणना की व्यवस्था समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

अब पुनः पूर्व प्रचलित स्लैब आधारित प्रणाली ही लागू रहेगी, जिसके अनुसार नगर निगम में 50 डेसिमल, नगर पालिका में 37.5 डेसिमल और नगर पंचायत में 25 डेसिमल तक स्लैब दर से मूल्यांकन किया जाएगा। इससे नगरीय क्षेत्रों में मूल्यांकन की जटिलता कम होगी और नागरिकों को सीधी राहत मिलेगी। बहुमंजिला भवनों में फ्लैट, दुकान अथवा कार्यालय के अंतरण के समय अब मूल्यांकन सुपर बिल्ट-अप एरिया के बजाय बिल्ट-अप एरिया के आधार पर होगा। यह प्रावधान लंबे समय से मांग में था, जिससे वर्टिकल डेवलपमेंट को गति मिलेगी और शहरी भूमि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा। साथ ही बहुमंजिला एवं कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट और प्रथम तल पर 10 प्रतिशत तथा द्वितीय तल एवं उससे ऊपर के तल पर 20 प्रतिशत की छूट के साथ मूल्यांकन करने का निर्णय लिया गया है, जिससे मध्यम वर्ग को किफायती दरों पर आवासीय एवं व्यावसायिक इकाइयाँ उपलब्ध होंगी।

कमर्शियल कॉम्प्लेक्सों में मुख्य मार्ग से 20 मीटर दूरी पर स्थित संपत्तियों के लिए भूखंड की गाइडलाइन दर में 25 प्रतिशत की कमी करने का भी निर्णय लिया गया है। यह दूरी कॉम्प्लेक्स के मुख्य सड़क की ओर स्थित निर्मित हिस्से से मापी जाएगी, जिससे वास्तविक बाज़ार स्थिति के अनुरूप मूल्यांकन संभव होगा। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने यह भी निर्देश दिए कि हाल ही में बढ़ाई गई दरों पर प्राप्त सभी ज्ञापनों और सुझावों का परीक्षण कर जिला मूल्यांकन समितियाँ 31 दिसंबर 2025 तक अपने संशोधित प्रस्ताव भेजें। इन प्रस्तावों के आधार पर राज्य में आगे की गाइडलाइन दरों की संरचना तैयार की जाएगी।

इस बैठक के साथ ही राज्य सरकार द्वारा गाइडलाइन दरों में किए गए कई जनहितैषी सुधार भी लागू हो चुके हैं। नजूल, आबादी और परिवर्तित भूमि पर पहले वर्गमीटर दर लागू होती थी, जिसे अब कृषि भूमि की तरह हेक्टेयर दर पर लागू किया जाएगा। इससे भूमि मूल्य में भारी कमी आई है और नागरिकों को वास्तविक राहत मिली है। उदाहरणस्वरूप रायपुर के वार्ड 28 में एक एकड़ भूमि का मूल्य पहले 78 करोड़ रुपये आंका जाता था, जो अब नए प्रावधानों के अनुसार केवल 2.4 करोड़ रुपये होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। परिवर्तित भूमि पर सिंचित भूमि के ढाई गुना मूल्य जोड़ने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। दो फसली भूमि पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत मूल्य जोड़ने, ट्यूबवेल, कुएं, वाणिज्यिक फसलों तथा वृक्षों के मूल्य को भूमि मूल्य में जोड़ने की व्यवस्था भी हटा दी गई है। कांकेर में दर्ज एक उदाहरण में 600 वृक्षों के 78 लाख रुपये मूल्य को अब रजिस्ट्री में शामिल नहीं किया गया, जिससे खरीदार को लगभग 8.58 लाख रुपये की सीधी राहत मिली और पेड़ों की कटाई रोकने में भी यह कदम सहायक सिद्ध होगा।

शहर से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में अब 25 से 37.5 डिसमिल तक की कृषि भूमि का मूल्यांकन वर्गमीटर के बजाय हेक्टेयर दर से किया जाएगा। बरौदा (रायपुर) में 37.5 डिसमिल भूमि का मूल्य पहले 26.75 लाख रुपये था, जो अब नए प्रावधानों के अनुसार मात्र 6.30 लाख रुपये होगा। तालाब अथवा मछली टैंक वाली भूमि पर 1.5 गुना दर लगाने का प्रावधान तथा बाउंड्री वॉल और प्लिंथ लेवल के मूल्य जोड़ने की व्यवस्था भी हटा दी गई है। नगरीय निकाय क्षेत्रों में पहले निर्मित संपत्तियों के लिए 21 प्रकार की दरें लागू थीं, जिन्हें घटाकर अब केवल दो प्रकार की दरें कर दिया गया है, जिससे मकानों का मूल्यांकन करना अब आम नागरिकों के लिए अत्यंत आसान हो गया है।

सरगुजा का अब तेजी से हो रहा विकास : अरुण साव

उप मुख्यमंत्री ने 82.24 करोड़ के कार्यों का किया लोकार्पण - भूमिपूजन

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सरगुजा संभागीय मुख्यालय अंबिकापुर में 82 करोड़ 23 लाख 71 हजार रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। उन्होंने शहर के स्वच्छता पार्क में 50 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित अटल परिसर के लोकार्पण के साथ ही लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के विभिन्न कार्यों का भूमिपूजन भी किया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े तथा पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल भी लोकार्पण-भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरगुजा तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। केवल 23 महीनों में ही अम्बिकापुर शहर के विकास के लिए 209 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा सरगुजा संभाग में सड़कों के कायाकल्प के लिए 1737 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि विष्णु के सुशासन में प्रदेश सरकार तेजी से विकास कार्यों को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि आज लोकार्पित और भूमिपूजन किए गए कार्यों से सरगुजा में न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि पर्यटन, कृषि और स्थानीय व्यापार को नई दिशा मिलेगी। महापौर मंजूषा भगत ने अपने संबोधन में कहा कि शहर के विकास के लिए स्वीकृत बड़े कार्यों से अम्बिकापुर का तेजी से विकास होगा और जन सुविधाएं बढ़ेंगी। उन्होंने स्वीकृत सभी कार्यों के लिए उप मुख्यमंत्री अरुण साव के प्रति शहरवासियों की ओर से आभार व्यक्त किया।

विधायक प्रबोध मिंज और रामकुमार टोप्पो, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव, छत्तीसगढ़ युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती निरूपा सिंह, कलेक्टर विलास भोसकर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल और नगर निगम के कमिश्नर डी.एन. कश्यप सहित पार्षदगण, जनप्रतिनिधि तथा गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री साव ने लोक निर्माण विभाग द्वारा कुल 27 करोड़ 94 लाख 86 हजार रुपए की लागत से बनाए जाने वाले छह सड़कों का भूमिपूजन किया।

नल जल योजनाओं से हर घर पहुंचेगा शुद्ध जल

उप मुख्यमंत्री साव ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत भिट्ठीकला, कंचनपुर, नवानगर, देवीटिकरी, तेंदुटिकरा, बकनाकला, बरगीडीह, चिरगा, गंगापुर, करांकी, दर्रीटोला, बतौली, नवडीहा, दोरना, तेंदूडांड, कुनकुरी, कछारडीह, डूमरभावना, लैगू एवं चैनपुर में कुल 32 करोड़ नौ लाख रुपए की नल-जल योजनाओं का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इन योजनाओं से हर घर में नल से शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

इनमें फरसाबहार धरमपुर मार्ग, लंबाई 4 किमी, लागत 602.58 लाख, बतौली-शांतिकुंज मार्ग, लंबाई 3 किमी, लागत 344.16 लाख, फ रसाबहार- जनरलगो सड़क, लंबाई 3.50 किमी, लागत 373.58 लाख, डूमरपाखना-पेण्डरमारी रोड, लंबाई एक किमी, लागत 260.56 लाख, कटकोना शिवान रोड, लंबाई 4.20 किमी, लागत 504.05 लाख तथा पोईबोहरा-गुढ़उपूरीगुड़ा- बुढ़ा गांव मार्ग, लंबाई 5 किमी, लागत 709.93 लाख शामिल हैं। इन सड़कों के निर्माण से क्षेत्र में आवागमन बेहतर होगा, व्यापारिक गतिविधियों को सुगमता मिलेगी और ग्रामीण संपर्क मार्ग मजबूत होंगे।

श्री साव ने अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 33 करोड़ 78 लाख 75 हजार रुपए की लागत के छह शहरी परियोजनाओं का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। उन्होंने 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित अटल परिसर के लोकार्पण के साथ ही 11 करोड़ 59 लाख रुपए के माँ महामाया कॉरिडोर निर्माण तथा दो करोड़ 39 लाख रुपए लागत के पुष्प वाटिका, सरगवा पार्क तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार कार्य का भूमिपूजन किया।

मुख्यमंत्री साय से क्रेडाई और रियल एस्टेट के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज शाम उनके निवास कार्यालय में क्रेडाई,रियल एस्टेट और बस्तर चेंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जगदलपुर के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। उल्लेखनीय है कि राज्य में 20 नवंबर 2025 से लागू नई गाइडलाइन दरों के संबंध में प्राप्त सुझावों, ज्ञापनों और आपत्तियों पर विचार करने हेतु मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक कल 07 दिसंबर 2025 को आयोजित की गई थी। बैठक में पंजीयन एवं मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल और जनहितैषी बनाने के उद्देश्य से कई व्यापक निर्णय लिए गए, जो 08 दिसंबर से तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। प्रतिनिधि मंडल ने सरकार द्वारा लिए गए उक्त महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुख्यमंत्री साय का आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी, वन मंत्री केदार कश्यप, उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन और विधायक किरण देव उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना : रायपुर-बलौदाबाजार के 800 यात्री बाबाधाम की यात्रा पर रवाना

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बुजुर्गों के लिए शुरू की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत रायपु व बलौदा बाजार के 800 यात्रियों का जत्था 6 दिसंबर को बाबाधाम की यात्रा पर रवाना हुआ। केबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने सभी यात्रियों को शुभकामनाएं भी दीं। इस मौके पर समाज कल्याण विभाग के संयुक्त संचालक अरविंद गेडाम व उपसंचालक सिनी वाली गोयल उपस्थित रहे।

यह यात्रा छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का एक हिस्सा है, जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त में प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा कराई जाती है। रायपुर 509 बलौदाबाजार 271 व अन्य 20 यात्रियों के साथ कुल 800 यात्रियों को रायपुर रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन द्वारा झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना किया गया। इस दौरान बाबाधाम के अलावा बजरंग बली मंदिर, अनुकूल ठाकुर जी सत्संग मंदिर के भी दर्शन करेंगे।

ट्रेन के रवाना होने के पूर्व मंत्री टंकराम वर्मा ने सभी यात्रियों से मुलाकात भी की। सभी से बातचीत कर यात्रा के लिए शुभकामनाएं दीं। इस मौके पर मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि 'मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना' के तहत चलाई गई विशेष ट्रेन को रायपुर रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देवघर (झारखंड) स्थित बाबा बैद्यनाथ पवित्र धाम के दर्शन हेतु प्रस्थान करने वाले श्रद्धालुओं में अद्भुत उत्साह और आस्था दिखाई दी। सभी यात्रियों के जीवन में यह यात्रा मंगलमय हो, भोलेनाथ की कृपा सदैव सभी पर बनी रहे, यही कामना है।

विद्यार्थियों में छिपे चैम्पियन को बाहर लाने में मददगार है खेल-कूद प्रतियोगिताएं

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने कहा है कि हर खिलाडी में एक चैम्पियन होता है, बस उस चैम्पियन का प्रोत्साहित करने और उसे बाहर लाने की जरूरत होती है। उन्होने कहा कि खेल-कूद प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में छिपे चैम्पियन को बाहर लाने में मददगार होती है।

डॉ. चंदेल ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों में अंतर्निहित खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। डॉ. चंदेल आज यहां कृषि विश्वविद्यालय के स्पोर्टस काम्प्लेक्स में विश्वविद्यालयीन खेल-कूद प्रतियोगिता 2025 का शुभारंभ कर रहे थे। कुलपति डॉ. चंदेल ने खेल ज्योति प्रज्ज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले चारों जोन की टीमों में शामिल खिलाड़ियों को खेल भावना की शपथ भी दिलाई।

विश्वविद्यालयीन खेल-कूद प्रतियोगिता - 2025 में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण जोन के अंतर्गत आने वाले समस्त महाविद्यालयों के 160 प्रतिभागी शामिल हुए हैं। 08 से 11 दिसम्बर, 2025 तक आयोजित होने वाली इस तीन दिवसीय विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता के अंतर्गत विभिन्न क्रीड़ा स्पर्धाओं का आयोजन किया जा रहा है। इस विश्वविद्यालय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के अंतर्गत व्यक्तिगत स्पर्धाओं में लम्बी कूद, ऊंची कूद, ट्रिपल जंप, भाला फेंक, गोला फेंक, डिस्क थ्रो, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, हर्डल दौड़ तथा 4.100 मीटर एवं 4.400 मीटर रिले दौड़ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। सामूहिक स्पर्धाओं के अंतर्गत वॉलीबाल, खो-खो, कबड्डी, बैडमिंटन तथा टेबल टेनिस स्पर्धाओं का आयोजन किया जा रहा है।

विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया और कहा कि विद्यार्थी जीवन में खेलों का बहुत महत्व है। इससे शरीर स्वस्थ एवं मजबूत बनता है एवं बच्चों में टीम स्पिरिट तथा खिलाड़ी भावना का विकास होता है जो भविष्य में उन्हें सफल एवं अनुशासित नागरिक बनने में योगदान देते हैं। उन्होंने प्रतिभागियों से आव्हान किया कि वे अपनी पूरी क्षमता तथा मेहनत के साथ प्रतियोगिता में भाग लें तथा सफलता अर्जित करें।

शुभारंभ समारोह में आयोजन समिति के अध्यक्ष अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ. संजय शर्मा ने स्वागत भाषण देते हुए आयोजन की रूप-रेखा प्रतिपादित की। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे ईमानदारी, निष्ठा और खेल भावना के साथ इस चार दिवसीय खेल-कूद प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करें। शुभारंभ समारोह में कृषि महाविद्यालय रायपुर की अधिष्ठाता डॉ. आरती गुहे, खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. एस.एस. सेंगर, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. अजय वर्मा, निदेशक शिक्षण डॉ. ए.के. दवे, संचालक अनुसंधान डॉ. वी.के. त्रिपाठी, निदेशक विस्तार डॉ. एस.एस. टूटेजा भी मौजूद थे।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रयासों से कवर्धा में महिला सशक्तिकरण को मिली नई दिशा

दो वर्षों में महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को लेकर किए गए कई महावपूर्ण पहल, महतारी वंदन से कवर्धा विधानसभा की माताओं बहनों को मिले 251.63 करोड़

- निःशुल्क सोनोग्राफी जांच शिविर से वनांचल में पहुंची स्वास्थ्य सुविधाएं
- स्वरोजगार के लिए 100 महिलाओं को सिलाई मशीन का वितरण
- 409 कन्याओं का करवाया गया सामूहिक विवाह
- लखपति दीदी योजना ने महिला समूहों को दिखाई आर्थिक प्रगति की राह

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा के महिला शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर किए गए सतत प्रयासों ने कवर्धा में महिला सशक्तिकरण को एक नई दिशा प्रदान की है। महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ना, उनके शिक्षा और रोजगार के लिए की गई पहल के साथ महतारी वंदन योजना ने महिलाओं को सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की पहचान बन चुकी महतारी वंदन योजना से कवर्धा विधानसभा की 1 लाख 30 हजार से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। उन्हें प्रति माह 1 हजार रुपये के मान से अब तक 251 करोड़ 63 लाख 96 हजार रुपये का भुगतान किया जा चुका है। योजना की 21 किश्तों की राशि खाते में दी जा चुकी हैं, और कुछ दिन पहले 22 वीं किश्त भी जारी कर दी गई है। कई महिलाएं इस राशि का उपयोग अपने बच्चों के बेहतर पढ़ाई लिखाई में कर रही हैं, तो कई ने घर के अन्य खर्चों को वहन करने में किया। सुदूर वनांचल क्षेत्रों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा शुरू की गई है, जिससे अब तक 1000 से अधिक महिलाओं को लाभ मिला है। समय पर होने वाली जांच से गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य की ठीक से मॉनिटरिंग संभव हो रही है। किसी प्रकार के जटिल और गंभीर मामलों में समय पर इलाज संभव हो सकता है। यह जांच शिविर जच्चा और बच्चा दोनों की सेहत की सुरक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। महिला स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कवर्धा की 100 से अधिक महिलाओं को उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने सिलाई मशीन वितरित किया है। ताकि वे अपना खुद का काम शुरू कर सकें। यह महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दृष्टि से अभिनव प्रयास है।

409 कन्याओं का करवाया गया सामूहिक विवाह

विजय शर्मा के प्रयासों से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत कवर्धा विधानसभा के 409 कन्याओं का सामूहिक विवाह धूमधाम से संपन्न कराया गया, जिसमें उपमुख्यमंत्री स्वयं बाराती बनकर शामिल हुए और नवयुगल दंपत्तियों को शुभाशीष प्रदान किया।

लखपति दीदी योजना ने महिला समूहों को दिखाई आर्थिक प्रगति की राह

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को स्व-सहायता समूहों से जोड़कर उन्हें सामाजिक-आर्थिक विकासमूलक योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। कवर्धा विधानसभा में 6,158 स्व-सहायता समूह बनाए जा चुके हैं। आजीविका से जुड़कर यहां की 13,924 महिलाएँ अब 'लखपति दीदी' बनकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हुई हैं।

महतारी सदन से मिली महिला सशक्तिकरण की नयी पहचान

उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत मंत्री विजय शर्मा के प्रयासों से कबीरधाम जिले को महतारी सदन योजना के अंतर्गत 19 महतारी सदनों की महत्वपूर्ण सौगात मिली है। यह योजना राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण के प्रति दूरदर्शी सोच और प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण बनकर उभरी है। जिले में अब तक निर्मित 05 महतारी सदन भवनों का वर्चुअल लोकार्पण मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा किया गया, जबकि शेष 14 महतारी सदनों का निर्माण कार्य 3 करोड़ 45 लाख रुपये की लागत से प्रगति पर है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक राजेश अग्रवाल द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित कर, 204 आकाशगंगा सुपेला, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक राजेश अग्रवाल shreekanchanpath2010@gmail.com, Mo - 9303289950